सुबह सवेरे

A Daily News Magazine
भोपाल
बुधवार, 16 जुलाई, 2025

भोपाल एवं इंदौर से एक साथ प्रकाशित

वर्ष 22, अंक 307, नगर संस्करण, पृष्ठ 8, मूल्य रू. 2

04 - पितृसत्ता का परिणाम है ऑनर किलिंग

05 - अमर्यादित नहीं हो सकती है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता

06 - अब हर दिन स्कूलों में ली जाएगी स्वच्छता की शपथ

07 - शासन की योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन कर...

subahsaverenews@gmail.com
facebook.com/subahsaverenews
www.subahsavere.news
twitter.com/subahsaverenews

सुप्रभात

मैं अपने
हृदय को
प्रेम के बगीचे में
ले जाता हूं

मैं अपने हृदय से
रस की नदी
बहाता हूं

मैं अपने हृदय के
गीत
सबको सुनाता हूं

मैं अपने हृदय में
वसंत को
बसाता हूं

मैं अपना हृदय
अपने प्यार को
समर्पित कर देता हूं ।

- दुर्गा प्रसाद झाला

प्रसंगवश

अब सुप्रीम कोर्ट के सुझाव पर अमल करे चुनाव आयोग..

संतोष कुमार पाठक

दरअसल, भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में चुनाव आयोग का काम ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं को वोटर लिस्ट में शामिल कर,उन्हें वोट देने के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित करना है। चुनाव आयोग का काम वोटर लिस्ट से जीवित मतदाताओं का नाम हटाना नहीं है।

बिहार में मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण अभियान-स्ढ्ढक्रके खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए देश की सर्वोच्च अदालत ने चुनाव आयोग को कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को लंबी सुनवाई करने और दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि वह मतदाता सूची पुनरीक्षण के लिए जरूरी मान्य दस्तावेजों में आधार कार्ड, राशन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड को भी शामिल करने पर विचार करे। देश की सर्वोच्च अदालत ने चुनाव आयोग से कई अहम मुद्दों पर जवाब दाखिल करने को भी कहा है। मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी।

हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण पर रोक नहीं लगाई है। यानी चुनाव आयोग द्वारा चलाया गया यह विशेष अभियान चलता रहेगा। लेकिन अदालत ने आधार कार्ड, राशन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड को भी मान्यता देने का सुझाव देकर बिहार के आम मतदाताओं की मुश्किलों को भी आसान करने का प्रयास किया है। इससे पूरी प्रक्रिया आसान होगी और वोटर लिस्ट को लेकर जिस तरह की आशंकाएं पैदा हो रही है, उसे भी कम करने में मदद मिलेगी।

दरअसल, भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में चुनाव आयोग का काम ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं को वोटर लिस्ट में शामिल कर, उन्हें वोट देने के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित करना है। चुनाव आयोग का काम वोटर लिस्ट से जीवित मतदाताओं का नाम हटाना नहीं है। चुनाव आयोग किसी भी मतदाता से उसका मताधिकार कतई नहीं छीन सकता है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान, बिहार सहित पूरे देश में आधार कार्ड को जिस तरह से बाकी सभी कार्डों, बैंक खातों और सरकारी योजनाओं से जोड़ा गया है, उसके बाद आधार कार्ड को पूरी तरह से खारिज करने से कई तरह के सवाल खड़े हो रहे थे। बिहार में कई जिलों में इस अभियान के तहत आधार कार्ड को स्वीकार किया जा रहा था और कई जिलों में नहीं किया जा रहा था, जिससे कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई थी। ऐसे में यह बहुत जरूरी माना जा रहा था कि चुनाव आयोग कोई बीच का रास्ता निकाले।

सुप्रीम कोर्ट ने भले ही SIR पर रोक नहीं लगाई हो लेकिन टाइमिंग को लेकर जो सवाल पूछे हैं, उससे चुनाव आयोग की इस पूरी कवायद पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव और चुनाव आयोग के इस अभियान को लेकर सुनवाई के दौरान कई महत्वपूर्ण सवाल भी पूछे। हालांकि जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस जॉयमाला बागची की पीठ ने साफ-साफ कहा कि वे संवैधानिक संस्था को वह करने से नहीं रोक सकते जो उसे करना चाहिए। लेकिन कोर्ट ने चुनाव आयोग को अपना जवाबी हलफनामा दायर करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है। वहीं याचिकाकर्ताओं को उसके एक सप्ताह बाद जवाब दाखिल करने के लिए कहा है।

यह मामला केवल बिहार तक ही सीमित रहने वाला नहीं है। आने वाले दिनों में दूसरे राज्यों में मतदाता सूची की समीक्षा कैसे होगी, यह बिहार के मॉडल पर निर्भर करेगा इसलिए सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले पर सबकी नजरें बनी रहेंगी।

हालांकि यह भी एक कड़वा सच है कि बिहार सहित देश के कई राज्यों में अवैध घुसपैठियों की भरमार हो गई है। भारत 70 के दशक से ही बांग्लादेश से आने वाले अवैध घुसपैठियों से त्रस्त रहा है और पिछले कुछ वर्षों के दौरान म्यामांर से भी रोहिंग्या मुसलमानों की घुसपैठ देश में बढ़ती जा रही है। देश के कई जिलों में इन अवैध घुसपैठियों की वजह से हालात काफी भयावह हो गए हैं, इसे नकारा नहीं जा सकता है। बिहार के भी कई जिले, अवैध घुसपैठियों से भरे पड़े हैं, इस सच्चाई को भी खारिज नहीं किया जा सकता। कहा जाता है कि बिहार के सीमांचल इलाकों में अवैध घुसपैठियों की संख्या तेजी से बढ़ी है लेकिन सच्चाई यह है कि बिहार का हर जिला बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों से पीड़ित है। बिहार के मिथिलांचल इलाके में भी अवैध घुसपैठियों की संख्या खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। लेकिन इस समस्या का समाधान कर पाना चुनाव आयोग के वश में नहीं है। इसके लिए केंद्र सरकार और केंद्रीय गृह मंत्रालय को विभिन्न एजेंसियों और राज्य सरकारों के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर अभियान चलाना होगा। एक तरफ सीमा से होने वाली घुसपैठ को हर हाल में रोकना होगा, दूसरी तरफ सीमावर्ती जिलों के प्रशासनिक ढांचे को भ्रष्टाचार मुक्त और चुस्त-दुरुस्त बनाना होगा। इसके साथ ही देश में घुस चुके घुसपैठियों को देश से हर कीमत पर बाहर भगाने के लिए भी एक व्यापक अभियान चलाना होगा। यह समय की मांग है कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को बाहर भगाने के लिए जल्द से जल्द इस तरह का अभियान बड़े पैमाने पर शुरू किया जाए।

(प्रभासाक्षी डॉट कॉम पर प्रकाशित लेख के संपादित अंश)

शुभ क्षण!

'गगन' जीतकर लौटे शुभांशु

- 18 दिन बाद लौटे, सकुशल धरती पर रखा अपना कदम
- शुभांशु मुस्कुराए, नजर आई तिरंगे की शान

कैलीफोर्निया के तट पर हुई स्पेसक्राफ्ट की सफल लैंडिंग

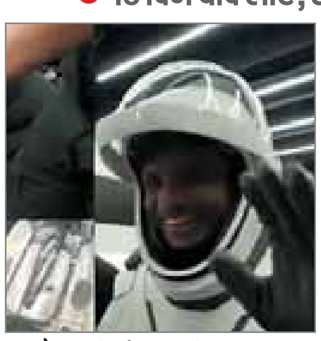

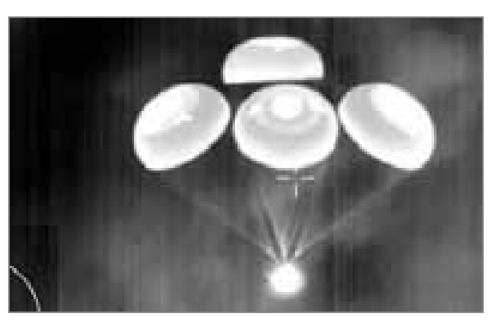

कैलीफोर्निया (एजेंसी)। शुभांशु शुक्ला सहित चार एस्ट्रोनॉट 18 दिन अंतरिक्ष में रहने के बाद पृथ्वी पर लौट आए हैं। करीब 23 घंटे के सफर के बाद ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट की दोपहर 3 बजे कैलीफोर्निया के समुद्र में लैंडिंग हुई। चारों एस्ट्रोनॉट एक दिन पहले शाम 4.45 बजे आईएसएस से पृथ्वी के लिए रवाना हुए थे। सभी एस्ट्रोनॉट 26 जून को भारतीय समय के अनुसार शाम 4.01 बजे आईएसएस पहुंचे थे। एक्सियम मिशन 4 के तहत 25 जून को दोपहर करीब 12 बजे ये रवाना हुए थे। स्पेसएक्स के फाल्कन-9 रॉकेट से जुड़े ड्रैगन कैप्सूल में इन्होंने कैनेडी स्पेस सेंटर से उड़ान भरी थी। आखिरकार वो ऐतिहासिक क्षण पूरी दुनिया ने देखा जब ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला और ड्रैगन अंतरिक्ष यान पर सवार एक्सिओम-4 क्रू मेंबर्स के साथ 18 दिनों धरती पर पहुंचे। ये अंतरिक्षयात्री प्रशांत महासागर में उतरे। एक्सिओम-4 मिशन में शुभांशु शुक्ला के साथ कमांडर पैगी व्हिट्सन, मिशन एक्सपर्ट पोलैंड के स्लावोज उज्नान्स्की-विस्नीव्स्की और हंगरी के टिबोर कापू भी शामिल थे। ये ड्रैगन 'ग्रेस' अंतरिक्ष यान से भारतीय समयानुसार सोमवार शाम 4.45 बजे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से धरती की ओर रवाना हुए थे।

मात्र 2.5 घंटे में पहुंचेंगे दिल्ली से पटना!

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारत में बुलेट ट्रेन का काम तेजी से चल रहा है। अहमदाबाद-मुंबई के बीच बन रही बुलेट ट्रेन परियोजना में एक नया अपडेट आया है। रेलवे अधिकारियों ने बताया है कि इस प्रोजेक्ट में जापानी शिंकानसेन ट्रेनों के ई 5 मॉडल का इस्तेमाल होगा। ये ई 5 मॉडल गुजरात सेक्शन में 2026-27 में ट्रायल रन के लिए उपयोग किए जाएंगे। इसके बाद भारत ई 10 मॉडल खरीदेगा। ये और भी आधुनिक ट्रेनें होंगी। ई10 शिंकानसेन ट्रेनें भारत और जापान में एक साथ 2030 में शुरू होने की संभावना है। मतलब, जिस साल ये ट्रेन जापान में शुरू होगी, उसी साल भारत में भी दौड़ेगी। यानी दिल्ली से पटना की 1,000 किमी दूरी मात्र 2.5 घंटे में पूरी की जा सकती है।

उत्तराखंड में 150 मीटर गहरी खाई में गिरी टैक्सी

- पिथौरागढ़ में 8 लोगों की मौत, 13 लोग सवार थे, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

पिथौरागढ़ (एजेंसी)। उत्तराखंड में मंगलवार शाम पिथौरागढ़ जिले में एक मैक्स जीप बेकाबू होकर 150 मीटर गहरी नदी में गिर गई। हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में एक स्कूली बच्ची समेत 4 महिलाएं हैं। जबकि 5 घायल हुए हैं। हादसा सोनी पुल के पास हुआ। जीप मुवानी से बकटा जा रही थी। जिसमें 13 लोग सवार थे। सूचना पाकर प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। एनडीआरएफ, पुलिस और अन्य रेस्क्यू टीमों ने घायलों को नदी से बाहर निकाला और उन्हें अस्पताल भिजवाया। मृतक बोकटा क्षेत्र के निवासी हैं। घायलों में तीन की हालत गंभीर है। सभी का मुवानी अस्पताल में इलाज चल रहा है। हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया, जीप शाम करीब 4 बजे यात्रियों को लेकर मुवानी से बकटा जा रही थी। जीप बकटा से थोड़ी ही दूर पर थी। तभी ड्राइवर संतुलन खो बैठा और जीप खाई में पलटते हुए नदी में जा गिरी। गाड़ी के परखच्चे

उड़ गए। नदी में घायलों और मृतकों का ढेर लग गया। फौरन पुलिस को सूचना दी। पुलिस एम्बुलेंस और राहत बचाव दल को लेकर मौके पर पहुंची। रेस्क्यू टीम ने मौके से 8 लाशें निकाली हैं। जबकि 5 लोग घायल हैं।

डीपी वर्ल्ड और जाफजा अधिकारियों से महत्वपूर्ण बैठक

मुख्यमंत्री ने 'भारत मार्ट' को बताया वैश्विक व्यापार का प्रवेशद्वार

मध्यप्रदेश को लॉजिस्टिक्स और निर्यात का हब बनाने की दिशा में मजबूत कदम

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने दुबई यात्रा के तीसरे दिन डीपी वर्ल्ड और जेबेल अली फ्री ज़ोन के वरिष्ठ अधिकारियों से भेंट कर 'भारत मार्ट' परियोजना और उससे जुड़ी लॉजिस्टिक्स संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा की। यह बैठक भारत के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को वैश्विक बाज़ार से जोड़ने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल मानी जा रही है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने भारत मार्ट को वैश्विक व्यापार का प्रवेशद्वार बताते हुए कहा कि यह आधुनिक व्यापार केंद्र भारतीय उत्पादों, विशेष रूप से खाद्य प्रसंस्करण, कृषि और हस्तशिल्प जैसे उत्पादों की मध्य पूर्व, अफ्रीका और यूरोप जैसे बाजारों तक सीधी पहुँच उपलब्ध कराएगा। भारत मार्ट 2026 में परिचालन में आएगा और 'लोकल से ग्लोबल' की नीति को नई दिशा देगा।

भारत मार्ट भारत और यूएई के बीच व्यापारिक संबंधों का प्रतीक- भारत मार्ट, जेबेल अली फ्री ज़ोन,दुबई में लगभग 2.7 मिलियन वर्ग फुट में विकसित किया जा रहा एक बहुआयामी अंतरराष्ट्रीय व्यापार केंद्र है। इसकी आधारशिला प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम द्वारा फरवरी 2024 में संयुक्त रूप से रखी गई थी। यह केंद्र डीपी वर्ल्ड द्वारा संचालित किया जा रहा है और इसमें 1500 से अधिक शोरूम, अत्याधुनिक गोदाम और कार्यालय सुविधाएं शामिल होंगी।

यह परियोजना भारतीय एमएसएमई को वैश्विक मंच प्रदान करने के लिए तैयार की जा रही है, जिससे वे अपनी गुणवत्ता युक्त वस्तुओं का निर्यात आसानी से कर सकें। भारत मार्ट, वैश्विक व्यापार में भारत की हिस्सेदारी को बढ़ाने वाला एक मजबूत स्तंभ बनेगा।

डीपी वर्ल्ड- भारत और मध्यप्रदेश के लिए संभावनाओं से भरा साझेदार

डीपी वर्ल्ड, दुबई स्थित एक अग्रणी वैश्विक लॉजिस्टिक्स और आपूर्ति श्रृंखला समाधान प्रदाता है, जो 78 से अधिक देशों में 100 से अधिक टर्मिनलों और पोर्ट्स का संचालन करता है। प्रति वर्ष 70 मिलियन टीईयू कंटेनर हैंडल करने वाली यह कंपनी विश्व की सबसे बड़ी पोर्ट ऑपरेटरों में गिनी जाती है।

भारत में संचालन

डीपी वर्ल्ड भारत के मुंबई, मुंद्रा, कोचीन, चेन्नई और विशाखापत्तनम जैसे प्रमुख बंदरगाहों पर छह टर्मिनलों का संचालन करती है। साथ ही यह कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स, कंटेनर फ्रेट स्टेशन और एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट सेवाओं का भी प्रबंधन करती है।

म.प्र. में ड्राय पोर्ट के विकास में दिखाई रूचि

डीपी वर्ल्ड ने मध्यप्रदेश में इनलैंड कंटेनर डिपो ,मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क ,कृषि-लॉजिस्टिक्स हब और ड्राय पोर्ट के विकास में गहरी रुचि दिखाई है। यह राज्य की लॉजिस्टिक्स और निर्यात नीति के अनुरूप है, और सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से दीर्घकालिक अधोसंरचना विकास को मजबूती देने वाला कदम है।

कांवड़ मार्ग में क्यूआर कोड पर गरम हुआ सुप्रीम कोर्ट

योगी सरकार को नोटिस, पूछा- ऐसा करना क्यों है जरूरी

नई दिल्ली (एजेंसी)। यूपी और उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा मार्ग पर दुकानों और रेस्तरां संचालकों को आदेश दिया गया है कि वे क्यूआर कोड लगाएं और नाम भी लिखें। यह मामला मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो अदालत ने उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। शीर्ष अदालत ने पूछा कि आखिर इसकी जरूरत क्या है। अब इस केस की अगली सुनवाई 22 जुलाई तय की गई है। न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश ने सुनवाई की।

पंजाब विधानसभा में नहीं पास हो पाया बेअदबी वाला विधेयक

भारी विवाद और टकराव के बाद सिलेक्ट कमेटी को भेजा गया

चंडीगढ़ (एजेंसी)। पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र में मंगलवार को धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी को लेकर पेश किए गए बिल पर बहस हुई। 14 जुलाई को मुख्यमंत्री भगवंत मान ने यह विधेयक पेश किया था। बहस के बाद भी विधेयक पास नहीं किया गया, बल्कि मुख्यमंत्री मान के प्रस्ताव पर इसे सिलेक्ट कमेटी को भेज दिया गया। सिलेक्ट कमेटी इस बिल पर काम करते हुए सभी धार्मिक संस्थाओं और लोगों से राय लेगी। इसके लिए 6 महीने का समय तय किया गया है। इसके बाद इस बिल को दोबारा विधानसभा में पेश किया जाएगा। स्पीकर कुलतार सिंह संधवां इस कमेटी का गठन करेंगे। इससे पहले बेअदबी बिल पर चर्चा के दौरान गरमागरम बहस हुई।

ट्रंप की धमकी, रूस से तेल खरीदा तो खैर नहीं

मास्को पर 100 फीसदी टैरिफ लगाने की चेतावनी

मास्को (एजेंसी)। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन में हमले कर रहे रूस के बीच चल रही जुबानी जंग में अब भारत और चीन जैसे देश भी फंस सकते हैं। ट्रंप ने कहा है कि रूस अगर 50 दिनों में यूक्रेन युद्ध को खत्म करने पर सहमत नहीं होता है तो अमेरिका मास्को के खिलाफ 100 फीसदी टैरिफ लगा सकता है। यही नहीं ट्रंप ने यह भी धमकी दी है कि अगर रूस 50 दिन में तैयार नहीं होता है तो उससे तेल खरीदने वाले देशों पर भी प्रतिबंध लगाया जाएगा। ट्रंप की इस धमकी का इशारा सीधे भारत और चीन की ओर है जो रूस से सबसे ज्यादा तेल खरीद रहे हैं। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद रूस भारत को अब

सबसे ज्यादा तेल का निर्यात कर रहा है। अमेरिका लगातार कई साल से भारत को धमका रहा है लेकिन दिल्ली ने वॉशिंगटन के आगे घुटने नहीं टेके हैं। ट्रंप ने नाटो के सेक्रेटरी मार्क रुट्टे से मुलाकात की है जहां पर उन्होंने नाटो के जरिए यूक्रेन को बड़े पैमाने पर हथियार भेजने का ऐलान किया है। ट्रंप ने कहा,हम रूस से बेहद नाखुश हैं। अगर रूस ने 50 दिन में डील नहीं किया तो उसके खिलाफ भारी टैरिफ लगाया जाएगा। यह टैरिफ 100 फीसदी होगा। इस दौरान ट्रंप और रुट्टे ने एक नई स्कीम का ऐलान किया जिसके तहत अमेरिकी हथियार यूक्रेन को नाटो के जरिए मिलते रहेंगे। वहीं अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वाइट हाउस के अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि की है कि ट्रंप रूस पर 100 फीसदी टैरिफ लगाएंगे, वहीं जो देश रूस से ऊर्जा खरीदते हैं, उनके खिलाफ सेकेंडरी प्रतिबंध लगाएंगे। हाल के दिनों में ट्रंप कई बार पुतिन पर अपना गुस्सा निकाल चुके हैं जो यूक्रेन में जंग को रोकने के लिए तैयार नहीं हैं। ट्रंप ने कहा कि पुतिन ने उन्हें निराश किया है। ट्रंप रूस और अन्य देशों पर प्रतिबंध की धमकी दे चुके हैं।

भोपाल का तापमान
अधिकतम 35°c
न्यूनतम 30°c

सुबह सवेरे

भोपाल ■ बुधवार, 16 जुलाई 2025

जो अग्नि हमें गर्मी देती है , हमें नष्ट भी कर सकती है ; यह अग्नि का दोष नहीं है।
चाणक्य नीति

नई तकनीक से कृषि में आएगा क्रांतिकारी परिवर्तन

भोपाल (नप्र)। नई तकनीकें न केवल समय की बचत करती हैं, बल्कि जीवन को सरल और समृद्ध भी बनाती हैं। मंगलवार को पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीमती कृष्णा गौर एक निजी उपकरण कंपनी द्वारा संचालित 'परिवर्तन यात्रा' के समापन अवसर पर निवास कार्यालय, भोपाल में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रही थीं।

राज्यमंत्री श्रीमती गौर ने कहा कि मशीनीकरण अब कृषि का अभिन्न अंग बन चुका है, जो किसानों की उत्पादकता बढ़ाने और उनकी जीवनशैली को बेहतर बनाने में सहायक है। उन्होंने विशेष रूप से महिला किसानों की सराहना करते हुए कहा कि आज वे भी आधुनिक मशीनों को अपनाकर खेती को आसान और सशक्त बना रही हैं। पावर टूल्स और कृषि उपकरणों की निर्माता कंपनी ने परिवर्तन यात्रा के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में तकनीकी जागरूकता फैलाने और कृषि के आधुनिकीकरण में अहम योगदान दिया है।

परिवर्तन यात्रा के तहत 5100 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करते हुए 35 जिलों में 1500 से अधिक किसानों से सीधा संवाद किया गया। इस पहल ने किसानों में नई तकनीकों को लेकर विश्वास और उत्साह उत्पन्न किया है। कार्यक्रम में भोपाल के पूर्व सांसद श्री आलोक संजर, उपकरण निर्माता कंपनी के एमपी एएसएम श्री अनीमेश वाघेला एवं भोपाल के अधिकृत डीलर भी उपस्थित रहे। राज्यमंत्री ने कंपनी को शुभकामनाएं देते हुए उम्मीद जताई कि ऐसे प्रयास किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएंगे और प्रदेश को तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर बनाएंगे।

● देश भर में बिहार वाला एसआईआर कराने की तैयारी

फॉर्म 6 और 8 में बदलाव के लिए बन गया टेम्पलेट

नई दिल्ली (एजेंसी)। बिहार में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) के तहत चुनाव आयोग ने मतदाता पंजीकरण के नियमों में बदलाव किया है। अब नए मतदाताओं और बाहर से बिहार में आने वाले वोटर्स को अपने बर्थ सर्टिफिकेट के साथ ही माता-पिता के जन्म प्रमाण से संबंधित विशेष घोषणा पत्र भी जमा करना होगा। यह नियम 24 जून को जारी एसआईआर निर्देशों के तहत लागू किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि यह बदलाव जल्द ही पूरे देश में लागू हो सकता है। नए नियम के अनुसार, बिहार में फॉर्म 6 (नए मतदाता

पंजीकरण) और फॉर्म 8 (निवास स्थानांतरण या मतदाता सूची में सुधार) के साथ एक अतिरिक्त घोषणा पत्र भरना जरूरी होगा।

राहुल गांधी को लखनऊ कोर्ट से मिल गई जमानत

● भारतीय सेना से जुड़ा है यह मामला

लखनऊ (एजेंसी)। कांग्रेस नेता राहुल गांधी मंगलवार को लखनऊ में एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट से जमानत मिल गई है। 20-20 हजार के दो

जमानतदारों के जरिए राहुल गांधी को जमानत मिली है। बता दें यह पेशी भारतीय सेना पर की गई टिप्पणी को लेकर दर्ज मानहानि मामले में हुई। राहुल गांधी पिछली पांच सुनवाइयों में कोर्ट में हाजिर नहीं हुए थे, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें समन जारी किया था। इस बार कोर्ट ने उनकी उपस्थिति अनिवार्य की है, जिससे पहले से ही कोर्ट परिसर में सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए। राहुल गांधी मंगलवार को दिल्ली से फ्लाइट के जरिए करीब 12.30 बजे लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अमौसी एयरपोर्ट पहुंचे। यहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। एयरपोर्ट से सीधे वह सिविल कोर्ट स्थित एमपी-एमएलए कोर्ट के लिए रवाना हुए। कोर्ट की कार्रवाई पूरी होने के बाद वह लखनऊ निवासी एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला के घर भी जा सकते हैं। शुभांशु हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष मिशन के लिए चुने गए हैं और राहुल गांधी उन्हें बधाई देने की योजना में हैं। बता दें कि यह पूरा मामला 2022 में राहुल गांधी के एक बयान से जुड़ा है। 16 दिसंबर 2022 को भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल ने कहा था कि यह आरोप लगाया था।

एक जिला-एक उत्पाद मध्यप्रदेश को मिला रजत पदक

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मार्गदर्शन में 'एक जिला-एक उत्पाद' योजना के अंतर्गत प्रदेश के उत्पादों की वैश्विक बाजारों में उपस्थिति दर्ज हो रही है।

मध्यप्रदेश ने अपनी विशिष्टता और योजनाओं के उत्कृष्ट क्रियान्वयन का प्रमाण प्रस्तुत करते हुए एक जिला एक उत्पाद पुरस्कार 2024 में राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश श्रेणी में रजत पुरस्कार प्राप्त किया। नई दिल्ली स्थित प्रतिष्ठित भारत मंडपम में एक भव्य समारोह में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने पुरस्कार प्रदान किया। यह पुरस्कार राज्य में एक जिला एक उत्पाद योजना के प्रभावशाली क्रियान्वयन, स्थानीय उत्पादों के ब्रांड निर्माण, रोजगार सृजन, और ग्रामीण व शहरी उद्यमिता को बढ़ावा देने के प्रयासों को मान्यता देने के लिए प्रदान किया गया।

दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता और भारत सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों एवं विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि भी इस अवसर पर उपस्थित थे। मध्यप्रदेश की ओर से यह प्रतिष्ठित पुरस्कार उद्योग विभाग, वाणिज्य एवं निवेश प्रोत्साहन नीति विभाग की उप सचिव, श्रीमती रूही खान ने प्राप्त किया।

प्रदेश अब लोकल से ग्लोबल की ओर- एक जिला-एक उत्पाद योजना में म.प्र. के उत्पादों को वैश्विक बाजार मिल रहा है। प्रदेश स्थानीय से ग्लोबल की ओर बढ़ रहा है। स्थानीय स्तर पर निर्यातकों का बड़ा समूह तैयार हो रहा है। कई उत्पादों को जी.आई. टैग मिला है जिसमें इन उत्पादों की वैश्विक मांग बढ़ी है। हस्तशिल्प एवं कृषि और खाद्य उत्पादों की पहचान बढ़ने के साथ कारीगरों और निर्माताओं के जीवन स्तर में भी सुधार हो रहा है।

ओडीओपी योजना में विशेष उत्पादों को उनके भौगोलिक, जैविकीय, प्राकृतिक या उत्पादन की विशेषताओं के कारण शामिल किया गया है। सभी जिलों में ओडीओपी योजना संचालित है, जिनमें हरी सब्जी, मोटे अनाज, क्राफ्टकला हथकरघा, हस्तशिल्प, उपकरण शामिल है। स्थानीय कलाकारों और उत्पादों को विशेष प्रोत्साहन दिया जा रहा है। अलग-अलग जिलों के 19 विशिष्ट उत्पादों को अब तक जीओ-ग्राफिकल इंडीकेशन्स (जीआई) टैग प्रदान किये गये है। इसमें चंदेरी साड़ी, बाग प्रिंट, नागपुरी संतरा, रतलामी सेंव, कड़कनाथ मुर्गा, चिन्नौर चावल, बुटिक प्रिंट, स्टोन क्राफ्ट, लेदर टॉय, बेल मेटल वेअर, महेश्वरी साड़ी, महोबा देशवारी पान, मुरैना गजक, सुंदरजा आम, शरबती गेहूँ, गोंड पेंटिंग, रॉट आयरन क्राफ्ट, हेन्डमेड कारपेट, वारासिवनी की हेंडलूम साड़ी शामिल है। इनमें से 7 उत्पाद ओडीओपी योजना में भी शामिल है।

मध्यप्रदेश ने 'एक जिला-एक उत्पाद' के अंतर्गत विश्व के प्रमुख बाजारों में अपनी पहचान बनाई है। वैश्विक बाजार तक पहुँचाने की दिशा में ठोस कदम भी उठाए हैं। राज्य के विभिन्न जिलों के उत्पादों को राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय पहचान मिली है। बुरहानपुर के उच्च गुणवत्ता वाले केले, रायसेन का सुगंधित बासमती चावल, और बालाघाट का प्रसिद्ध चिनौर चावल इन उत्पादों में प्रमुख हैं। मध्यप्रदेश के उत्पादों की पहचान अब सीमित नहीं रही, बल्कि ये राज्य की आर्थिक प्रगति, रोजगार अवसरों और निर्यात क्षमता को मजबूती दे रहे हैं।

एक जिला-एक उत्पाद योजना अब एक जनभागीदारी आधारित आंदोलन बन चुकी है। इसमें कारीगरों, महिला समूहों, एफपीओ, स्टार्टअप्स और स्थानीय उद्यमियों की सक्रिय भूमिका रही है। राज्य सरकार ने एक जिला-एक जिला उत्पाद को स्थानीय से वैश्विक बनाने की दिशा में अनेक कदम उठाए हैं। उत्पाद आधारित प्रशिक्षण, ब्रांडिंग और पैकेजिंग सुधार, डिजिटलीकरण और निर्यात को प्रोत्साहित करने हेतु लॉजिस्टिक सहयोग भी राज्य शासन द्वारा दिया जा रहा है।

मध्यप्रदेश न केवल संस्कृति और शिल्प की धरती है, बल्कि एक उभरता हुआ औद्योगिक और निर्यातक राज्य भी है। मध्यप्रदेश सरकार की यह उपलब्धि 'स्थानीय हाथों से वैश्विक मंच तक' की परिकल्पना को साकार कर रही है और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक सशक्त कदम है।

प्रदेश में इतने विविध उत्पाद हैं जिन्हें विश्व स्तर पर ले जा सकते हैं। 'एक जिला, एक उत्पाद' एक अनूठी पहल है और किसी अन्य देश में ऐसा नहीं है। प्रत्येक जिले की अपनी अलग विरासत है। उत्पादों की ब्रांडिंग और गुणवत्ता पर काम किया जा रहा है। पैकेजिंग और ब्रांडिंग में सुधार किया जा रहा है ताकि उत्पादों को उनकी उच्च गुणवत्ता के लिए दुनिया भर में सम्मान मिले। ओडीओपी पर्यटन को बढ़ावा देने में मदद करेगा।

ओडीओपी उत्पादों को आगे बढ़ाने के तरीके सीखने और अनुकरण करने में मदद के लिए एक सर्वोत्तम प्रथाओं का संग्रह तैयार किया गया है। केंद्र, सरकार ने 750 से अधिक जिलों से 1,200 से अधिक अनूठे उत्पादों की पहचान की है, जो कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, हथकरघा, हस्तशिल्प आदि क्षेत्रों में हैं। इन प्रयासों का उद्देश्य मूल्य संवर्धन, विपणन को बढ़ावा देना और स्थानीय उत्पादों को वैश्विक बाजारों से जोड़ना है। सिंगापुर, न्यूयॉर्क, वैंकूवर, मिलान, कुवैत, बहरीन और जापान में ओडीओपी वॉल्स स्थापित किए गए हैं। ओडीओपी उत्पाद अब सिंगापुर के मुस्तफा सेंटर और सेंटर पॉइंट मॉल जैसे खुदरा दुकानों पर उपलब्ध हैं। ओडीओपी पुरस्कारों के लिए 1 अप्रैल से 11 जून 2024 के बीच राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से कुल 641 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें जिलों से 587, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से 31 और विदेशों में भारतीय मिशनों से 23 प्रविष्टियां शामिल थीं।

भारतीय नर्स निमिषा की मौत की सजा टली

● दोनों देशों के धर्मगुरुओं ने की बातचीत, हत्या के मामले में मारी जानी थी गोली

सना (एजेंसी)। यमन में मौत की सजा पाने वाली केरल की नर्स निमिषा प्रिया की मौत की सजा फिलहाल टाल दी गई है। उसे 16 जुलाई को सजा-ए-मौत दी जानी थी। न्यूज एजेंसी ने मंगलवार को सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक्टिविस्ट ग्रुप और प्रभावशाली धार्मिक नेताओं ने इस मामले में दखल दिया, जिसके बाद निमिषा प्रिया की मौत की सजा स्थगित कर दी गई है। इससे पहले निमिषा को मौत की सजा से बचाने के लिए डिप्लोमैटिक लेवल पर भी कई कोशिशें की गई थीं। खबर यह भी है कि पीड़ित का परिवार अभी तक क्षमादान या ब्लड मनी स्वीकार करने के लिए सहमत नहीं हुआ है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यमन से चर्चित सूफी

विद्वान शेख हबीब उमर बिन हाफिज बातचीत कर रहे हैं। बातचीत में यमन के सुप्रीम कोर्ट के एक जज और मृतक के भाई भी शामिल हैं। शेख हबीब को बातचीत के लिए मुफ्ती मुसलियार ने मनाया। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कंथापुरम के ग्रैंड मुफ्ती एपी अबूबकर मुसलियार और यमन से चर्चित सूफी विद्वान शेख हबीब उमर बिन हाफिज इस मसले पर बातचीत कर रहे हैं। इसमें यमन के सुप्रीम कोर्ट के एक जज और मृतक के भाई भी शामिल हैं। यमन शेख हबीब को बातचीत के लिए मुफ्ती मुसलियार ने मनाया। ऐसा भी पहली बार हुआ है जब पीड़ित परिवार का कोई करीबी सदस्य बातचीत को तैयार हुआ है। यह बातचीत शरिया कानून के तहत हो रही है, जो पीड़ित परिवार को दोषी को बिना किसी शर्त के या फिर ब्लड मनी के बदले में माफ करने का कानूनी अधिकार देता है। भारतीय नर्स निमिषा 2017 से जेल में बंद हैं, उन पर यमन के नागरिक तलाल अब्दो महदी को ड्रग का ओवरडोज देकर हत्या की थी।

नए बीजेपी अध्यक्ष की चर्चा ने बढ़ाया सस्पेंस

● मोदी कैबिनेट में फेरबदल की भी है तैयारी, बनाया बड़ा प्लान

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष को लेकर चर्चाओं का दौर जारी है। इसी बीच सरकार राज्यपालों में भी बदलाव कर रही है और राज्यसभा के लिए नेता चुने जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि यह सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाले कैबिनेट में संभावित फेरबदल के संकेत हो सकते हैं। हालांकि, इसे लेकर भाजपा या एनडीए सरकार के किसी दल की ओर से आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि इन बदलावों के जरिए कैबिनेट फेरबदल के लिए जमीन तैयार की जा रही है। हाल ही में हरियाणा, गोवा के लिए राज्यपाल और लद्दाख के लिए उपराज्यपालों की नियुक्ति की है। इससे एक दिन पहले ही उज्ज्वल निकम, मीनाक्षी जैन, हर्षवर्धन श्रृंगला और सी सदानंद मास्टर को राज्यसभा भेजा गया।

मुख्यमंत्री नीतिश के लिए 'सॉफ्ट' हुए तेजस्वी यादव

● अचानक बदले लालू के छोटे लाल, 'खेला' का है प्लान

पटना (एजेंसी)। बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव , मुख्यमंत्री नीतिश कुमार पर लगातार हमलावर हैं। पटना में व्यापारी विक्रम झा की हत्या के बाद तेजस्वी और भी अधिक आलोचना कर रहे हैं। हालांकि, इंडिया ब्लॉक की एक मीटिंग में तेजस्वी ने महागठबंधन के नेताओं से नीतिश कुमार पर अधिक तीखे हमले न करने की बात कही है। वे चाहते हैं कि बीजेपी नेताओं को मुख्य रूप से निशाना बनाया जाए। ऐसा माना जा रहा है कि तेजस्वी को शायद फिर से महागठबंधन में नीतिश कुमार के लौटने की उम्मीद है। दरअसल, पटना में हाल ही में एक व्यापारी विक्रम झा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसके बाद तेजस्वी यादव ने नीतिश कुमार को अचेत मुख्यमंत्री बताया। उन्होंने सोशल मीडिया साइट पर लिखा कि पटना में व्यवसायी विक्रम झा की गोली मारकर हत्या!

स्पेन यात्रा का पहला दिन

मुख्यमंत्री डॉ. यादव 16 से 19 जुलाई तक स्पेन प्रवास पर रहेंगे

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 16 से 19 जुलाई 2025 तक स्पेन के आधिकारिक दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव प्रदेश में निवेश के माध्यम से औद्योगिक विकास और रोजगार सृजनकी दिशा में सतत् रूप से प्रयासरत् है। स्पेन प्रवास के दौरान वे मैड्रिड में आयोजित 'इन्वेस्ट इन मध्यप्रदेश' बिजनेस फोरम को संबोधित करेंगे और उद्योग, पर्यटन, खेल, संस्कृति तथा फिल्म निर्माण से जुड़े विषयों पर उच्चस्तरीय बैठकों में भाग लेंगे। मुख्यमंत्री दुबई से रवाना होकर देर रात स्पेन की राजधानी मैड्रिड पहुंचेंगे।

स्पेन प्रवास के प्रथम दिन 16 जुलाई की शुरूआत मुख्यमंत्री डॉ. यादव से भारत के राजदूत श्री दिनेश के. पटनायक शिष्टाचार भेंट करेंगे। इसके बाद वे 'इन्वेस्ट इन मध्यप्रदेश' बिजनेस फोरम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इस सेशन में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा पर्यटन, औद्योगिक नीति एवं निवेश, आईटी और अधोसंरचना सेक्टर पर प्रेजेन्टेशन होगा।

बिजनेस फोरम की शुरुआत मध्यप्रदेश शासन के सचिव एवं मुख्यमंत्री के सचिव श्री इलैयाराजा टी. के स्वागत भाषण से होगी। स्पेन-इंडिया काउंसिल फाउंडेशन के अध्यक्ष श्री जुआन इग्नासियो एंत्रेकानालेस भी फोरम को संबोधित करेंगे। नेचर बायोफूड्स के सीईओ श्री रोहन ग्रोवर द्वारा अनुभव साझा किये जाएंगे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव फोरम में उपस्थिति उद्योगपतियों को मध्यप्रदेश में विभिन्न सेक्टर्स में निवेश के अवसरों पर विस्तृत जानकारी देंगे। नेटवर्किंग लंच में मुख्यमंत्री डॉ. यादव स्पेन के प्रमुख उद्योगपतियों एवं विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों से संवाद करेंगे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव खेल सेक्टर में विख्यात स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डिज़ाइन एवं कंसल्टिंग फर्म 'पॉपुलस' के प्रजेंटेशन में भाग लेंगे। यह प्रजेंटेशन श्री जोर्ज बेटनकौर द्वारा दिया जाएगा। जिसमें मध्यप्रदेश में आधुनिक खेल अधोसंरचना विकास पर चर्चा की जाएगी।

'बरसाती नदियाँ और सबको पीछे छोड़ चुका है आदमी' काव्य संग्रह लोकार्पित

भोपाल। आईसेक्ट पब्लिकेशन, वनमाली सृजन पीठ, रबीन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में युवा कवि संजय सिंह राठौर के कविता संग्रह 'बरसाती नदियाँ और युवा रंगकर्मी विक्रांत भट्ट के कविता संग्रह सबको पीछे छोड़ चुका

है आदमी' का लोकार्पण टैगोर विश्वविद्यालय के कथा सभागार में समारोह पूर्वक किया गया।

इस अवसर पर वरिष्ठ कवि- कथाकार, निदेशक विश्व रंग एवं रबीन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय के कुलाधिपति संतोष चौबे ने लोकार्पण समारोह की अध्यक्षता करते हुए कहा कि संजय की कविताओं में मजदूर वर्ग की चिंता, उनके संघर्ष, परिवार माता-पिता पास पड़ोस अपने परिवेश के प्रति प्रेम परिलक्षित होता है, वही बाजारवाद के विरुद्ध भी उनकी कविताओं में जोर-शोर से बात होती है। विक्रांत की कविताओं में नाटकीयता के बिंब होते हैं।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि साहित्य अकादमी, मध्यप्रदेश शासन के निदेशक डॉ. विकास दवे ने कहा कि संजय जी की कविताओं में प्रतीकों का बखूबी प्रयोग हुआ है, जिसके माध्यम से वह अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करते हैं, उन्होंने उनकी कविता 'टांड और बोनसाई' का जिक्र करते हुए यह बात कही। उन्होंने उनकी कविता किराएदार को भी रेखांकित किया। वही विक्रांत की कविता में चांद कई तरह से कई प्रतिकों के रूप में आया है।

कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि वरिष्ठ कथाकार एवं वनमाली सृजन पीठ, भोपाल के अध्यक्ष मुकेश वर्मा ने कहा कि दोनों कवियों की रचनाओं में दुख और करुणा केंद्र में है, लेकिन दुख और करुणा के साथ दोनों का ट्रीटमेंट अलग-अलग है। दोनों ही कवि अंतर्मुखी है और लगातार अपने आप से संवाद करते हैं, जो पाठ को तक सीधे संप्रेषित होता है।वरिष्ठ कला समीक्षक एवं रंग संवाद के संपादक विनय उपाध्याय विक्रांत की कविताओं पर टिप्पणी की वहीं युवा कवि मुदित श्रीवास्तव ने संजय सिंह राठौर की कविताओं को रेखांकित करते हुए अपनी बात विस्तार से रखी।संजय सिंह राठौर ने अपनी कविताओं बोनसाई, अपना शहर, मां और किताब आदि का पाठ किया।विक्रांत भट्ट ने अपनी कविताओं लिक्विड प्रेम, अब प्लूटो के बारे में नहीं पढ़ाया जाता, पहले से कहीं ज्यादा आगे आदि का पाठ किया।

कार्यक्रम में स्वागत वक्तव्य आईसेक्ट पब्लिकेशन की प्रबंधक एवं वनमाली सृजन पीठ की राष्ट्रीय संयोजक सुश्री ज्योति रघुवंशी ने दिया। आईसेक्ट पब्लिकेशन के वरिष्ठ प्रबंधक श्री महीप निगम ने आभार व्यक्त किया।

बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट

मुंबई में समुद्र के नीचे 21 किमी टनल तैयार

मुंबई (एजेंसी)। मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की शुरुआती 21 किमी टनल बनकर तैयार हो गई है। रेल मंत्रालय के अनुसार, यह टनल घनसोली के बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स और शिलफाटा के ठाणे के बीच बनी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी फोटो भी शेयर की हैं। इसके अलावा प्रोजेक्ट के तहत 310 किलोमीटर का वायाडक्ट (ऊंचा पुल) भी बन गया है। पटरियां

बिछाने, ओवरहेड इलेक्ट्रिक वायर, स्टेशन और पुलों का निर्माण तेजी से चल रहा है। महाराष्ट्र में काम तेजी से पूरा हो रहा है। ट्रेन संचालन और कंट्रोल सिस्टम के लिए उपकरणों की खरीद की प्रक्रिया भी तेजी से चल रही है। मुंबई-अहमदाबाद रूट पर जापान की नेक्स्ट जनरेशन ई10 शिंकानसेन बुलेट ट्रेन चलेगी। जापान फिलहाल ई10 मॉडल पर काम कर रहा है। यह बुलेट ट्रेन मौजूदा ई3 और ई5 की तुलना में काफी तेज और मॉडर्न होगी।

मंत्री ने की उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा

मंत्री इंदर सिंह परमार ने सार्थक ऐप पर अनुचित रूप से फर्जी उपस्थिति दर्ज करने वाले प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक, अधिकारी, कर्मचारी और अतिथि विद्वानों पर कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए

भोपाल (नप्र)। उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं आयुष मंत्री श्री इन्दर सिंह परमार ने मंत्रालय में, उच्च शिक्षा विभाग के विभिन्न विभागीय विषयों एवं गतिविधियों की समीक्षा की।

उच्च शिक्षा मंत्री श्री परमार ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय में लंबित विभिन्न प्रकरणों की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों के निलंबन से संबंधित गंभीर एवं अनावश्यक रूप से लंबित विभागीय प्रकरणों को, सामान्य प्रशासन के नियमानुरूप समय पर निराकृत करने के निर्देश भी दिए। श्री परमार ने जनभागीदारी समिति के नियमों का पुनर्वलोकन कर, वर्तमान परिदृश्य अनुरूप समसामयिक बनाने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने को कहा।

मंत्री श्री परमार ने सार्थक ऐप पर अनुचित रूप से फर्जी उपस्थिति दर्ज करने वाले प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक, अधिकारी, कर्मचारी और अतिथि विद्वानों पर कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

श्री परमार ने क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक कार्यालयों के सुदृढ़ीकरण के लिए आवश्यक कार्ययोजना बनाकर क्रियान्वयन करने को कहा। श्री परमार ने उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने की दृष्टि से, महाविद्यालयों में एकल संकाय को बहुसंकाय में उन्नयन करने की कार्यवाही को यथाशीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए।

बैठक में अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा श्री अनुपम राजन एवं आयुक्त उच्च शिक्षा श्री प्रबल सिपाहा सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

सभी विद्युत कंपनियों में अंशदायी कैशलेस स्वास्थ्य योजना स्वीकृत : ऊर्जा मंत्री तोमर

नियमित कार्मिक सहित संविदा कार्मिक, पेंशनर और उनके परिजन होंगे लाभान्वित, क्रियान्वयन की प्रक्रिया प्रारंभ

भोपाल (नप्र)। ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया है कि प्रदेश के सभी 6 विद्युत कंपनियों में अंशदायी कैशलेस स्वास्थ्य योजना स्वीकृत कर दी गई है। मध्यप्रदेश पॉवर जनरेटिंग कंपनी ने प्रदेश की समस्त विद्युत कंपनियों में कार्यरत अभियंता व कार्मिकों के लिए बहुप्रतीक्षित पॉवर कंपनी अंशदायी कैशलेस स्वास्थ्य योजना (एमपीपीसीएचएस) के क्रियान्वयन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है।

लगभग एक लाख 82 हजार होंगे लाभार्थी– मंत्री श्री तोमर ने बताया है कि इस योजना का लाभ प्रदेश की 6 विद्युत कंपनियों में कार्यरत नियमित कार्मिकों, संविदा कार्मिकों व विद्युत कंपनियों के पेंशनरों और उनके परिजन को मिलेगा। इनकी संख्या लगभग एक लाख 82 हजार है। उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश पॉवर जनरेटिंग कंपनी को प्रदेश की विद्युत कंपनियों में पॉवर कंपनी अंशदायी कैशलेस स्वास्थ्य योजना लागू करने की जिम्मेदारी दी गई है।

कार्यान्वयन सहायता एजेंसी के लिये ई–टेंडर जारी

मध्यप्रदेश पॉवर जनरेटिंग कंपनी के प्रबंध संचालक मनजीत सिंह ने जानकारी दी कि पॉवर कंपनी अंशदायी कैशलेस स्वास्थ्य योजना के कार्यान्वयन के लिये 15 जुलाई को ई-टेंडर जारी कर दिया गया है। इस योजना के कार्यान्वयन सहायता एजेंसी (आईएसए) चयन के लिये भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) द्वारा लाइसेंस प्राप्त किसी मौजूदा तृतीय पक्ष प्रशासक (टीपीए) या उसकी होल्डिंग कंपनी या उसकी सहायक कंपनी या उसकी समूह कंपनी, जिन्हें इस क्षेत्र में कार्य करने का वृहद् अनुभव हो, से टेंडर आमंत्रित किए गए हैं। पॉवर कंपनी अंशदायी कैशलेस स्वास्थ्य योजना के लिए प्री-बिड मीटिंग 24 जुलाई को होगी।

विद्युत कंपनियों के लिए पॉवर कंपनी अंशदायी कैशलेस स्वास्थ्य योजना के क्रियान्वयन करने को इच्छुक कंपनियां 18 अगस्त तक टेंडर प्रक्रिया में अपनी निविदा जमा कर सकेंगी। आगामी 20 अगस्त को ई-टेंडर खोले जाएंगे। पॉवर जनरेटिंग कंपनी के प्रबंध संचालक श्री सिंह ने बताया है कि योजना एक अक्टूबर 2025 तक प्रारंभ करने का लक्ष्य है।

माखनलाल पत्रकारिता विश्वविद्यालय में प्रशासनिक पुनर्गठन

तीन विभागाध्यक्षों को मिले नए प्रभार डॉ. पी. शशिकला बनी कुलसचिव

भोपाल (नप्र)। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय में कार्य दक्षता और प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से प्रशासनिक पुनर्गठन किया गया है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने 11 जुलाई 2025 को तीन विभागाध्यक्षों को नए प्रभार सौंपने का आदेश जारी किया। इन बदलावों को विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली को और अधिक प्रभावी और समन्वित बनाने की दिशा में एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है।

नए दायित्वों की जानकारी

नवीन मीडिया प्रौद्योगिकी विभाग की विभागाध्यक्ष प्रो. डॉ. पी. शशिकला को कुलसचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। अभी तक वे डीन (अकादमिक) का पद संभाल रहीं थी। नया दायित्व विश्वविद्यालय के प्रशासनिक संचालन में एक महत्वपूर्ण भूमिका मानी जा रही है। कंप्यूटर अनुप्रयोग विभाग के विभागाध्यक्ष प्रो. डॉ. मनीष महेश्वरी अब तक डीन (छात्र कल्याण) थे। अब उन्हें नया पद डीन (अकादमिक) का दिया गया है।

मीडिया प्रबंधन विभाग के विभागाध्यक्ष प्रो. डॉ. अविनाश वाजपेयी कुलसचिव रहे। अब उन्हें डीन (छात्र कल्याण) का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है।

महत्वपूर्ण है यह बदलाव

विश्वविद्यालय प्रशासन का मानना है कि यह पुनर्गठन न केवल प्रशासनिक संतुलन को बेहतर बनाएगा, बल्कि शैक्षणिक और छात्रहित से जुड़े कार्यों को भी सुचारु रूप से संचालित करने में मदद करेगा।

कॉलेज छात्राओं से दोस्त के घर में रेप किया था

भोपाल में अश्लील वीडियो बनाए, धर्म बदलने का दबाव डाला, पुलिस ने कोर्ट को बताया

भोपाल (नप्र)। कॉलेज छात्राओं से दुष्कर्म कर वीडियो के जरिए ब्लैकमेल करने वाले मामले में जहांगीराबाद थाना पुलिस ने जिला न्यायालय में चालान पेश किया है। पुलिस ने फरहान खान, साहिल खान, सैयद अली अहमद, साद उर्फ शम्सउद्दीन, मोहम्मद नबील और अबरार को आरोपी बनाया है। सभी आरोपी जेल में बंद हैं। जहांगीराबाद थाने के जांच अधिकारी ने पीड़िताओं और उनके परिजन के दर्ज बयान, कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर), वीडियो फुटेज और फोटोग्राफ साक्ष्य के तौर पर न्यायालय में पेश किए गए हैं। आरोपियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में पेश किया गया।

रेप के बाद वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया

जहांगीराबाद पुलिस ने चालान में कोर्ट को बताया कि पीड़िता को लेकर आरोपी फरहान दोस्त के घर गया था। उसके दोस्त के घर पहले से ही कुछ और दोस्त मौजूद थे। पीड़िता को अलग कमरे में ले जाकर रेप किया। रेप के बाद जबरदस्ती वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करते हुए इस्लाम धर्म अपनाने का दबाव बनाया। हालांकि, मामले में पुलिस ने सभी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और सभी आरोपी सलाखों के पीछे हैं। पुलिस अलग-अलग एंगल से मामले की जांच कर रही है। जांच में भी पीड़िता के साथ ब्लैकमेलिंग और मुस्लिम धर्म अपनाने को लेकर दबाव बनाने की बात भी सामने आ रही है।

तीन लड़कियों से एक साथ रेप किया

इससे पहले पुलिस जांच के दौरान मुख्य आरोपी फरहान के मोबाइल में एक वीडियो ऐसा मिला था, जिसमें वह एक साथ तीन लड़कियों के साथ रेप कर रहा है। उन्हें बेरहमी से पीट रहा है। एक अन्य वीडियो में आरोपी इंदौर की पीड़िता से रेप करने के साथ ही उसे सिगरेट से दाग रहा है। आरोपी लड़कियों के साथ क्रूरता करता था। उन्हें मारता-पीटता था। वीडियो भी बनाता था और अपने मोबाइल फोन में सेव कर लेता था।

पीड़िताओं के वीडियो आरोपी ने एक अलग फोल्डर में सेव कर रखे थे। पूछताछ में उसने बताया कि वह गांजा पीने का आदी है। इंदौर की पीड़िता को उसने कई बार मजबूर कर गांजा और शराब पिलाई है। उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। पुलिस को गुमराह करने के लिए आरोपी ने यह भी बताया कि वह इंदौर की पीड़िता से प्यार करता था। उससे शादी करना चाहता था।

तीन थानों में दर्ज है रेप–लव जिहाद के केस

कॉलेज छात्राओं से रेप और लव जिहाद के केस भोपाल के तीन थानों में दर्ज हैं। इससे पहले 19 जून को अशोका गार्डन थाने ने भी इसी केस की जांच पूरी कर आरोपियों के खिलाफ अभियोग पत्र दाखिल किया गया था। वहीं, 12 जून को बागसेवनिया थाना पुलिस ने फरहान और साहिल के खिलाफ जांच पूरी कर कोर्ट में चालान पेश किया था।

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, यह पूरा मामला अलग-अलग थानों में दर्ज छात्राओं की शिकायतों से जुड़ा हुआ है, जिसमें सोशल मीडिया पर दोस्ती के बाद अश्लील वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करने की साजिश रची गई थी।

सपा प्रदेशाध्यक्ष बोले: सरकारी खर्च के बिल पोर्टल पर डिस्प्ले हों

शहडोल में ड्रायफ्रूट और पेंट घोटाले के बाद सरकारी सिस्टम में पारदर्शिता जरूरी

भोपाल (नप्र)। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. मनोज यादव ने मप्र के सरकारी विभागों में होने वाले खर्च के पूरे बिल-वाउचर संबंधित विभाग के पोर्टल पर (पब्लिक डोमेन में) डिस्प्ले करने की मांग की है। भोपाल में सपा के प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डॉ. यादव ने कहा- शहडोल में ड्रायफ्रूट घोटाला और सीधी में पेंट घोटाला सामने आने के बाद ये जरूरी हो गया है कि जहां सरकारी पैसा खर्च हो उसके व्यय से संबंधित पूरे दस्तावेज पब्लिक डोमेन में रहें।

डॉ. यादव ने कहा कि शहडोल जिले में ऐसे मामले सामने आए, जिसमें चार लीटर पेंट को पोतने के लिए 150 से ज्यादा लेबर लगाई गई। अधिकारी अगर जाते हैं तो उनके लिए 14 किलो ड्राई फ्रूट का बिल लगाया जाता है। इससे समझ में आता है कि सरकारी पैसे का किस तरह से बंदर बांट किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि चाहे नेता हो या अधिकारी। किसी भी दौरे पर जाएं तो उनके स्वागत में जो पैसा खर्च हो रहा है उसकी जानकारी पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए। सरकारी विभागों में हो रहे खर्च का लेखा-जोखा भी आना चाहिए।

उमा भारती को सम्मेलन में नहीं बुलाया

डॉ. यादव ने भोपाल में आयोजित महिला सशक्तिकरण सम्मेलन में पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती को नहीं बुलाने पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि उमा भारती पिछड़े वर्ग से आती हैं। उनको सम्मेलन में नहीं बुलाया जाता, तवज्जो नहीं दी जाती है। क्या यही भाजपा की ट्रेनिंग है। पार्टी के मंत्री और नेता पहले भी महिलाओं के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणियां कर चुके हैं।

सांसद पर एक्शन ले बीजेपी

डॉ. यादव ने कहा कि भाजपा महिला सशक्तिकरण की बात करती है। सशक्त महिलाओं के सम्मान की बात करती है। मोदी जी भोपाल में आकर महिला सशक्तिकरण सम्मेलन करते हैं, लेकिन यदि कोई महिला आवाज उठाती है तो उस आवाज को दबाया जाता है। भाजपा के सांसद हमारी गर्भवती बहन के बारे में कहते हैं कि आपको उठवा लिए जाएगा। उनको धमकी दी जाती है कि अगर रोड ठीक नहीं है तो भी आपने अपनी बात कही क्यों?

उन्होंने कहा कि यही भाजपा का असली चाल-चरित्र और चेहरा है। सांसद का दोबारा बयान आया, उसमें भी वे माफी मांगने की बजाय अपने बयान पर कायम रहने की बात कर रहे हैं। सांसद को उस बहन से माफी मांगनी चाहिए। यदि वे माफी नहीं मांगते हैं, तो भाजपा को अपने सांसद पर कार्यवाही करनी चाहिए।

भोपाल में स्कूल बैग का वजन तौलने पहुंचे कांग्रेसी

कहा– मापदंडों से अधिक वजन के बैग ढो रहे बच्चे जागरूकता अभियान कागजों पर

भोपाल (नप्र)। भोपाल में मंगलवार को कांग्रेस नेताओं ने स्कूल पहुंचकर बच्चों के बैग का वजन चेक किया। उन्होंने तौल कांटे पर बैग रखकर देखा। जिसमें पाया कि बच्चों के बैग निर्धारित मापदंडों से अधिक है।

एमपी कांग्रेस के प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी, अभिनव बरोलिया, कुंदन पंजाबी और विक्रम चौधरी ने आरोप लगाया कि 16 जून से प्रदेश में स्कूल बैग के वजन को लेकर स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शुरू किया जाने वाला जागरूकता अभियान एक माह बीत जाने के बाद भी केवल कागजों और आदेशों में ही चल रहा है।

उन्होंने कहा कि जमीनी हकीकत में इस पर कोई अमल नहीं हो रहा है। शिक्षा माफियाओं ने कमीशन के लालच में न सिर्फ निजी स्कूलों को, बल्कि शासकीय स्कूलों, जिनमें सीएम राइज स्कूल भी शामिल हैं, को निशाना बनाया हुआ है।

डीईओ कार्यालय से 500 मीटर दूर किया प्रदर्शन– विवेक त्रिपाठी ने बताया कि जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से महज 500 मीटर की दूरी पर शासकीय पीएमश्री स्कूल और निजी स्कूल के छात्र भी शासन के निर्धारित मापदंडों से कई गुना अधिक वजन के स्कूल बैग ढोने को मजबूर हैं।

छोटे बच्चों के नाजुक कंधों पर अत्यधिक वजन लादने की वजह से कई बच्चे पढ़ाई और खेलकूद की उम्र में ही डॉक्टर और अस्पताल के चक्कर लगाने को मजबूर हो रहे हैं। उन्होंने भाजपा सरकार, प्रशासन और बाल आयोग पर इस गंभीर विषय पर 'मूक दर्शक' बने रहने का आरोप लगाया।

विवेक त्रिपाठी ने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि शिक्षा माफिया अनावश्यक किताबों की खरीद में कमीशनखोरी के लालच में छात्रों के जीवन और स्वास्थ्य के साथ खुला खिलवाड़ कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि शासकीय स्कूलों में मुफ्त मिलने वाली किताबों के वितरण में भी नियमों का उल्लंघन चिंताजनक है।

भोपाल स्टेशन को मेट्रो स्टेशन से जोड़ने का प्लान

सब–वे या फुटओवर ब्रिज बनेगा, सीधे एक दूसरे से कनेक्ट हो सकेंगे

भोपाल (नप्र)। भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के बाद भोपाल स्टेशन को भी मेट्रो स्टेशन से जोड़ने का प्लान है। यहां सब-वे या फुटओवर ब्रिज बनेगा। ताकि, मेट्रो और रेलवे स्टेशन एक-दूसरे से कनेक्ट हो सके।

मेट्रो अफसरों के मुताबिक, भोपाल रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर-6 के पास मेट्रो का अंडरग्राउंड स्टेशन बनेगा। इसकी तैयारियां भी चल रही हैं। जब यात्री मेट्रो से रेलवे स्टेशन आएंगे-जाएंगे तो उन्हें फुटओवर ब्रिज या सब-वे की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में उन्हें काफी लंबा चलना नहीं पड़ेगा।

2 प्लान पर काम

रेलवे और मेट्रो स्टेशन को एक-दूसरे से कनेक्ट करने के लिए मेट्रो कॉरपोरेशन दो प्लान पर काम कर रहा है। यदि सिर्फ 6 नंबर प्लेटफार्म से मेट्रो स्टेशन को जोड़ना पड़ा तो यहां फुटओवर ब्रिज ही बनाया जाएगा। यात्री ट्रैक के ऊपर से गुजरते हुए मेट्रो स्टेशन तक पहुंच सकेंगे, लेकिन यदि प्लेटफार्म नंबर-6 के साथ 1 को भी मेट्रो स्टेशन से जोड़ने की प्लानिंग बनी तो फिर सब-वे बनाया जाएगा, जो अंडरग्राउंड रहेगा।

जाम से भी मिलेगी राहत

फुटओवर ब्रिज या सब-वे बनने के बाद यात्रियों को पैदल घूमकर नहीं आना पड़ेगा। साथ ही उन्हें जाम से भी राहत मिलेगी।

आरकेएमपी को जोड़ा है स्काई वॉक से

मेट्रो से रानी कमलापति और भोपाल रेलवे स्टेशन को जोड़ा जाएगा। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का काम चल रहा है। यहां 70 मीटर लंबा स्काई वॉक रखा गया है, जो दोनों स्टेशनों को कनेक्ट कर रहा है। इससे यात्रियों को बिना किसी परेशानी से एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक पहुंचने में आसानी होगी। ऐसा ही उपयोग भोपाल रेलवे स्टेशन पर भी हो रहा है। हालांकि, यह काम मौजूदा प्रोजेक्ट में शामिल नहीं है। इसलिए अलग से प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। इसलिए सब-वे और फुटओवर ब्रिज पर चर्चा की जा रही है।

मुख्यमंत्री ने विश्व युवा कौशल दिवस पर दीं शुभकामनाएं

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों विशेष रूप से युवाओं को शुभकामनाएं दीं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सोशल मीडिया के माध्यम से कहा कि वर्ष 2025 की थीम एआई (आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस) और डिजिटल कौशल से युवा सशक्तिकरण है। वर्तमान समय में एआई देश-प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई दिशा प्रदान कर रही है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि युवाओं को असीमित अवसर मिलें, इस उद्देश्य से राज्य सरकार तकनीकी-व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण को गति प्रदान कर रही है और प्रदेश के युवाओं के उज्ज्वल भविष्य के लिए हरसंभव कदम उठा रही है।

एमपी हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने संजीव सचदेवा

जस्टिस विवेक कुमार सिंह की भी नियुक्ति, हाईकोर्ट में अब 34 हुई जजों की संख्या

जबलपुर (नप्र)। जस्टिस संजीव सचदेवा मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बनाए गए हैं। सोमवार को केंद्र सरकार ने उनकी नियुक्ति को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है।

जस्टिस संजीव सचदेवा को 24 मई 2025 को एक्टिंग चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया था। वे तत्कालीन चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत के रिटायरमेंट के बाद से चीफ जस्टिस का दायित्व संभाल रहे हैं। इससे पहले भी वे 9 जुलाई 2024 से 24 सितंबर 2024 तक प्रदेश के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश का दायित्व संभाल चुके हैं। 30 मई 2024 को जस्टिस संजीव सचदेवा का दिल्ली हाईकोर्ट से मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में ट्रांसफर हुआ था।

इसके साथ ही केंद्र सरकार ने मध्यप्रदेश हाइकोर्ट को एक और जज दिया है। जस्टिस विवेक कुमार सिंह की मध्यप्रदेश में नियुक्ति की गई है। वे अभी मद्रास हाईकोर्ट में हैं, जिनका ट्रांसफर जबलपुर किया गया है। अब मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में जजों की संख्या बढ़कर 34 हो गई हैं।

भोपाल में राज्यपाल दिलाएंगे शपथ

जानकारी के मुताबिक जस्टिस सचदेवा को भोपाल में राज्यपाल शपथ दिलाएंगे। हालांकि, इसकी डेट अभी फाइनल होना बाकी है। जबकि जस्टिस विवेक कुमार सिंह को जबलपुर में ही जस्टिस सचदेवा शपथ दिलाएंगे।

नगर परिषद इंदरगढ़ के प्रभारी सीएमओ निलंबित

भोपाल (नप्र)। दतिया जिले के नगर परिषद इंदरगढ़ के प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी महेन्द्र सिंह यादव को अपने कर्तत्व्यों में लापरवाही बरतने पर नगरीय प्रशाासन विकास आयुक्त श्री संकेत भोंडवे के निर्देश पर निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय संभागीय कार्यालय ग्वालियर निर्धारित किया गया है।

नगर परिषद इंदरगढ़ में तालाब का निर्माण कराया जा रहा था। निर्माण के दौरान बरसात के मौसम में तालाब में पानी का भराव हुआ। सुरक्षा उपायों में लापरवाही बरतते हुए निर्माण कार्य के दौरान रेलिंग व बेरिगेटिंग की व्यवस्था नहीं गई। व्यवस्था के अभाव में छोटी बच्चियों के डूबने की घटना हुई। इसी के साथ प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी (सीएमओ) ने अपने कार्यकाल में नियम विरूद्ध कर्मचारियों की स्थापना में प्रशासनिक कार्य किये। जांच में प्रभारी नगर पालिका अधिकारी महेन्द्र सिंह यादव दोषी पाये गये।

प्रदेश के 183 नगरीय निकायों में 218 पिंक टॉयलेट

भोपाल(नप्र)। प्रदेश में नगरीय क्षेत्रों में सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं को सार्वजनिक शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मिशन पिंक टॉयलेट प्रारंभ किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 183 नगरीय निकायों में 218 पिंक शौचालय संचालित हो रहे हैं। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने इस मिशन में 100 करोड़ रूपये के निवेश की कार्ययोजना तैयार की है। मिशन के माध्यम से प्रदेश के सभी निकायों में मिशन पिंक टॉयलेट तैयार किये जायेंगे।

संपादकीय

पायलटों को दोषी ठहराने की साजिश ?

अहमदाबाद में एयर इंडिया की उड़ान क्र. AI-171 के भीषण हादसे में 270 लोगों की जान चली जाने और उड़ान भरते ही विमान के क्रैश हो जाने की विरल घटना की जांच जिस दिशा में जाती दिख रही है, उससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि जांच एजेंसी एएआईबी की अंतिम रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन यह कोशिश होती साफ दिख रही है कि इस विमान को बनाने वाली बोइंग और बीमा कंपनियों को किसी भी तरह से मुआवजा देने से या तो बचा लिया जाए या फिर वह न्यूनतम हो। इस पूरी जांच का अमेरिकी मीडिया में जिस एंगल से कवरेज हो रहा है, वह भी इसी तरफ संकेत करता है। विमान निर्माता बोइंग कंपनी भी अमेरिकी है। सारी कोशिश इस बात की होती दिख रही है कि दुर्घटना का दोष विमान के पायलटों के मत्थे मढ़ दिया जाए, क्योंकि वे दोनों ही पायलट अब दिवंगत हो चुके हैं और उनका पक्ष जानने का कोई तरीका नहीं है। गौरतलब है कि भारत के भीषणतम विमान हादसों में से एक अहमदाबाद विमान दुर्घटना की जांच एएआईबी (एयरक्राफ्ट एक्सिडेंट इंवेस्टिगेशन ब्यूरो) कर रहा है। इसकी प्राथमिक जांच रिपोर्ट पर सवाल उठाए जा रहे हैं। जबकि रिपोर्ट अभी सार्वजनिक हुई भी नहीं है कि अमेरिकी मीडिया इस हादसे का सारा दोष दिवंगत पायलटों पर डालने की साजिश में लगा है। यह आशंका यह आशंका एविएशन एक्सपर्ट की ओर से भी जताई जा रही है। अब तक जांच में महत्वपूर्ण क्लू यह है कि हादसे की वजह फ्यूल स्विच ऑफ होना था। जब फ्यूल ही नहीं मिला तो इंजन बंद हो गए और उड़ान भरने के कुछ सेकंडों में विमान नीचे आ गिरा। अब सवाल यह कि क्या विमान बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर का फ्यूल स्विच पायलटों ने जानबूझकर बंद किया? या फिर किसी तकनीकी खराबी के कारण इंजन बंद हो गया? जांच रिपोर्ट में इसका सीधा जवाब देते हुए, इसके लिए 'ट्रांजिशन' शब्द का इस्तेमाल किया गया है, न कि 'मैनुअल स्विच-ऑफ' का। जबकि वॉयस डेटा रिकॉर्डर में दोनों पायलटों के बीच बातचीत का जो हिस्सा जारी किया गया है, उससे जाहिर है कि किसी पायलट ने फ्यूल स्विच बंद किया है, इसका सवाल ही नहीं पैदा होता। ऐसे में पायलटों के सिर हादसे का ठीकरा फोड़ने के पीछे कोई बड़ी कारपोरेट साजिश तो नहीं है? अमेरिका में भी इस पर बड़ी बहस जारी है। लेकिन सबसे संदिग्ध सवाल वॉल स्ट्रीट जर्नल जैसी पश्चिमी मीडिया की जल्दबाजी की वजह से पैदा हो रहा है। इस अखबार ने प्रारंभिक जांच रिपोर्ट आने से पहले ही दुर्घटना का दोष पायलटों पर डालना शुरू कर दिया था और दावा किया गया कि विमान में कोई खराबी नहीं थी। यह भी कहा गया कि सॉफ्ट वेयर बंद होने से भी विमान के इंजन बंद हो सकते है। एएआईबी की रिपोर्ट में कहा कि 08:08:42 यूटीसी पर विमान की गति 180 नॉटिकल मील प्रति घंटा थी। इसके तुरंत बाद, इंजन 1 और इंजन 2 के फ्यूल कटऑफ स्विच 'रन' से 'कटऑफ' में चले गए। इससे टेकऑफ के बीच में ही इंजन बंद हो गए और विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया।

एविएशन समुदाय के लोगों का मानना है कि पायलटों पर दोष डालने से विमान निर्माता कंपनी, एविएशन रेगुलेटर्स और इंश्योरेंस कंपनियों को फायदा हो सकता है। उन्हें कम पैसा देना पड़ेगा और कानूनी झंझटों से भी मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन मैकेनिकल खराबी पाई जाती है, तो उन पर मुकदमे हो सकते हैं और करोड़ों रुपये का जुर्माना भी लग सकता है। पायलटों को दोषी ठहराने से बोइंग कंपनी देनदारियों से बच जाएगी। ऐसा हुआ तो मामला भोपाल गैस कांड की तरह होगा, जहां यूका मुआवजा देने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाती रही।

पितृसत्ता का परिणाम है ऑनर किलिंग

नजरिया

चित्रा माली

लेखिका महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के कोलकाता क्षेत्रीय केंद्र की प्रभारी हैं।

मानवाधिकार संस्था ह्यूमन राइट्स वाच, ऑनर किलिंग या सम्मान हत्या को इस प्रकार से परिभाषित करती है। 'सम्मान के लिए किए गए अपराध, हिंसा के वे मामले हैं, जिन्हें परिवार के पुरुष सदस्यों ने अपने ही परिवार की महिलाओं के खिलाफ इसलिए किया है, क्योंकि उनके अनुसार उस महिला सदस्य के किसी कृत्य से समूचे परिवार की गरिमा (इज्जत) और सम्मान को ठेस पहुंची है। इसका कोई भी कारण हो सकता है जो उस महिला सदस्य पर हमले को उचित ठहराने के लिए पर्याप्त है कि उसके किसी कदम से परिवार की इज़्ज़त को ठेस लगी हो'। अभी हाल ही में टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव की उसके ही पिता ने गोली मार कर हत्या कर दी है। इसकी कई वजह गिनाई जा रही हैं जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण पिता की इच्छा के विरुद्ध या कहें पितृसत्तात्मक व्यवस्था के विरुद्ध जाकर टेनिस अकादमी को चलाना है और सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना है।

ऑनर किलिंग इस शब्द को हमने कई बार सुना है। इस शब्द के निहितार्थ से भी हम कुछ हद तक वाकिफ़ हैं। ऑनर किलिंग का मतलब है,'परिवार समुदाय और जाति के सम्मान के लिए की गई हत्या'। महिला संगठनों के अनुसार प्रति वर्ष भारत में 20 हजार से अधिक महिलाओं को ऑनर किलिंग के नाम पर मारा जाता है। ऑनर किलिंग वह हत्या होती है जिसमें महिला और पुरुष दोनों में से कोई भी या दोनों को परिवार,वंश समुदाय के लोगों के द्वारा मौत के घाट उतार दिया जाता है लेकिन इसकी सबसे अधिक शिकार महिलाएं होती हैं। ऑनर किलिंग तब की जाती है जब कोई परिवार के सदस्यों की इच्छा के विरुद्ध जाकर अपनी मर्जी से कोई कार्य करता है खासकर शादी, और वो भी अन्य जाति या धर्म में या कोई शादी करने के लिए घर छोड़ देता है सामान्य भाषा में कहें तो भाग जाता हैं। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के अनुसार पूरे विश्व में सर्वाधिक हत्याएं,सम्मान के लिए की गई हत्याएं होती हैं।

मानवाधिकार संस्था ह्यूमन राइट्स वाच,ऑनर किलिंग या सम्मान हत्या को इस प्रकार से परिभाषित करती है। 'सम्मान के लिए किए गए अपराध,हिंसा के वे मामले हैं, जिन्हें परिवार के पुरुष सदस्यों ने अपने ही परिवार की महिलाओं के खिलाफ इसलिए किया है, क्योंकि उनके अनुसार उस महिला सदस्य के किसी कृत्य से समूचे परिवार की गरिमा (इज्जत) और सम्मान को ठेस पहुंची है। इसका कोई भी कारण हो सकता है जो उस महिला सदस्य पर हमले को उचित ठहराने के लिए पर्याप्त है कि उसके किसी कदम से परिवार की इज़्ज़त को ठेस लगी हो'। अभी हाल ही में टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव की उसके ही पिता ने गोली मार कर हत्या कर दी है। इसकी कई वजह गिनाई जा रही हैं जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण पिता की इच्छा के विरुद्ध या कहें पितृसत्तात्मक व्यवस्था के विरुद्ध जाकर टेनिस अकादमी को चलाना है और सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना है। राधिका की अपनी स्वतंत्रता पहचान थी और वह आज की आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और सशक्त नारी थी। लेकिन पितृसत्तात्मक व्यवस्था में पले बढ़े पुरुषों को यह नागवारा लगता है और उसी का परिणाम राधिका की हत्या है। इस व्यवस्था के विरुद्ध 18 नवंबर 1982 को पटना की किरण सिंह ने अपने पिता धरमनाथ सिंह,पटना विश्वविद्यालय के उपकुलपति, बिहार सरकार और पटना के पुलिस महानिरीक्षक के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की थी। किरण सिंह ने कहा कि मेरे पिता श्री धरमनाथ सिंह (जयनगर,बिहार),पटना विश्वविद्यालय के उपकुलपति और पटना के पुलिस अधिकारियों ने मेरे मौलिक अधिकारों का हनन और उन पर हमला किया है। मैं किरण सिंह 25 वर्ष की हूं और पटना विश्वविद्यालय के प्राणी विज्ञान विभाग में

पीएच.डी. की शोधार्थी हूं। मैं पटना के गणेशदत्त सिंह महिला छात्रावास में रहती हूं। मुझे 400 रुपये प्रतिमाह शोध वृत्ति मिलती है। मैं उसी से अपना गुजारा करती हूं। पिछले एक साल से मैंने अपने पिता से कोई आर्थिक मदद नहीं ली है। 14 अक्टूबर 1982 को मैंने अपने सहपाठी अनवर अहमद से शादी के पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) के लिए पटना न्यायालय में आवेदन किया था। मैं माननीय महोदय के समक्ष ये बातें रखना चाहती हूं कि मेरे पिता श्री धरमनाथ सिंह,पटना विश्वविद्यालय के कुलपति, उपकुलपति और पुलिस अधिकारियों के द्वारा-भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त जीवन और आजादी के मेरे मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है। देश के किसी भी हिस्से में रहने,घूमने-फिरने,शांति से जायज काम करने और वैध करार (विवाह) करने,न्याय पाने के संविधान प्रदत्त अधिकारों का हनन किया जा रहा है। अनवर अहमद के जीने और घूमने-फिरने की आजादी के अधिकारों का हनन किया जा रहा है। गणेशदत्त महिला छात्रावास के बाशिंदों के जीने,आजादी से घूमने-फिरने की स्वतंत्रता, जायज कार्य करने की आजादी और निजता के अधिकारों का हनन किया जा रहा है। दो भिन्न समुदायों के सदस्यों के अपनी मर्जी से विवाह के अधिकार को हिंसक तरीके अपनाकर विरोध किया जा रहा है और पटना शहर में साम्प्रदायिक कटुता और तनाव फैलाने की कोशिश की जा रही है। मुझे आप तक पहुंचने से रोका गया। मैं आपसे नम्रतापूर्वक निवेदन करती हूं कि मेरी जान व शरीर की सुरक्षा के साथ-साथ मेरे घूमने-फिरने,निवास और कामकाज करने के मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए बिहार सरकार को आदेश जारी करे,ताकि मैं अपने निवास-स्थल पर लौटकर शोधकार्य जारी रख सकूँ और देश के नागरिक होने के नाते अपने अधिकारों का उपयोग कर सकूँ। बिहार सरकार अनवर अहमद के लिए उपरोक्त आशय का आदेश जारी करे ताकि उनकी छिपकर रहने की मजबूरी खत्म हो। बिहार सरकार गणेशदत्त सिंह महिला छात्रावास में रहने वाली लड़कियों खासकर किरण अग्रवाल, मणिमाला और सरोज के लिए उपरोक्त आशय का आदेश जारी करे। बिहार सरकार मुझे मेरे पिता श्री धरमनाथ सिंह,भाई, अन्य सगे-संबंधियों और उनके द्वारा तैनात गुंडों की हिंसा और धमकियों से बचाने का आदेश जारी करे। ऐसे किसी भी शासकीय या न्यायिक आदेश को रद्द करने का आदेश जारी करे जो न्याय के खिलाफ जाता हो या जिसका दुरुपयोग सम्यक कानूनी प्रक्रिया या मुझे, अनवर अनवर अहमद और गणेशदत्त छात्रावास के निवासियों को परेशान करने के लिए किया जा सकता है। न्यायालय ने किरण सिंह की याचिका को जनहित याचिका मानते हुए सभी आरोपियों के नाम नोटिस जारी किया। (इस केस को विस्तार से मानुषी जनवरी-फरवरी 1983 के 14वेंअंक में पढ़ा जा सकता है) किरण सिंह के साथ जो हुआ वह बतौर नागरिक मौलिक अधिकारों का हनन था। इसे महज व्यक्तिगत या पारिवारिक मामला समझकर नकारा नहीं जा सकता है। इस याचिका के इतने वर्षों बाद भी महिलाओं के लिए उनके मौलिक अधिकारों का हनन सामान्य रोजमर्रा की बात हैं। बहुत कम महिलाएं अपने अधिकारों के लिए अपने परिवार से और समाज से लड़ने का साहस जुटा पाती हैं अन्यथा उसी व्यवस्था में अपने अलग अस्तित्व को बनाए रखने का प्रयास करती हैं। राधिका यादव के पूर्व भी ऑनर किलिंग की कई हत्याएं हुई हैं जिनको हमारे समाज ने सामान्य मानकर नज़रअंदाज़ कर दिया है और खासकर महिलाओं ने भी कभी इसे अपने नागरिक मौलिक अधिकारों का हनन मानकर इस व्यवस्था के विरुद्ध कोई प्रतिरोध नहीं किया है। राधिका यादव की हत्या पर विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बहस जारी है जिसमें राधिका के पक्ष के साथ साथ उसके पिता के पक्ष को भी सहानुभूति के साथ रखा जा रहा है। राधिका यादव की हत्या को महज परिवारिक हत्या नहीं कहा जा सकता है, यह पितृसत्तात्मक हत्या है जिसमें किसी भी महिला का आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होना, पिता की इच्छा के विरुद्ध जाकर स्वयं निर्णय लेने का साहस करना और महत्वाकांक्षी होना खलल उत्पन्न करता है।

बुनियाद ही कमजोर हो तो इमारत कैसे होगी बुलंद?

सरोकार

डॉ. चन्दर सोनाने

लेखक मप्र जनसंपर्क विभाग के सेवानिवृत्त अधिकारी हैं।

केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय के राष्ट्रीय सर्वेक्षण परख में हाल ही में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। सर्वेक्षण में यह पता लगा है कि कक्षा तीसरी के 45 प्रतिशत छात्र 99 तक के अंक बढ़ते या घटते क्रम में नहीं रख पाते। इसी कक्षा के 42 प्रतिशत छात्र 2 अंकों की संख्याएँ जोड़-घटा भी नहीं सकते। छठी कक्षा के 47 प्रतिशत बच्चे 10 तक के पहाड़े भी नहीं सुना पाते।

उक्त सर्वेक्षण गत 4 दिसम्बर को देश के 36 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के 781 जिलों में स्थित 74,229 स्कूलों में हुआ था। इसमें कक्षा तीसरी, छठी और नौंवी के 21.15 लाख छात्र शामिल हुए थे। कुल 2.70 लाख शिक्षक और स्कूल प्रमुखों की भी भागीदारी इस सर्वेक्षण में रही। इस सर्वे के नतीजों में कक्षा तीसरी और कक्षा नौवीं में पंजाब राज्य का प्रदर्शन देशभर में सबसे अच्छा रहा। कक्षा छठी में केरल के छात्रों का प्रदर्शन देशभर में सबसे अच्छा रहा।

कक्षा तीसरी में पढ़ने वालों बच्चों में टॉप-5 राज्यों के नाम है- पंजाब, हिमाचल प्रदेश, केरल, मणिपुर और राजस्थान। इसके साथ ही बॉटम-5 राज्यों के नाम इस प्रकार है- मेघालय, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, बिहार और गुजरात। कक्षा तीसरी के सर्वेक्षण में 50 प्रतिशत बच्चे ही 100 रूपए तक का लेनदेन कर पाते हैं। अर्थात 50 प्रतिशत बच्चे 100 रूपए का लेनदेन करने में नाकाम पाए गए। सर्वेक्षण में यह भी पाया गया कि 58 प्रतिशत छात्र ही 2 अंकों का जोड़ घटाव कर पाते है। अर्थात 42 प्रतिशत छात्र 2 अंकों का जोड़ घटाव करने में असमर्थ पाए गए। सर्वे में यह भी पाया गया कि कक्षा तीसरी में पढ़ने वाले छात्रों में शहरी क्षेत्र से ग्रामीण बच्चे आगे पाए गए।

कक्षा छठी में हुए सर्वे में देशभर में टॉप-5 राज्य इस प्रकार हैं- केरल, पंजाब, दमन-दीव, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश। इसी प्रकार बॉटम-5 राज्य इस प्रकार हैं- झारखंड, नागालैंड, उत्तराखंड, गुजरात और तमिलनाडु। इस सर्वे में यह भी पाया गया कि इस कक्षा के 51 प्रतिशत बच्चे मूल्यों के प्रति जागरूक हैं। जैसे कतार में खड़े होना, डस्टबिन का उपयोग, मदद के लिए तैयार। अर्थात 49 प्रतिशत बच्चे मूल्यों के प्रति उदासीन पाए गए। इस कक्षा के 29 प्रतिशत बच्चे ही आधा और चौथाई का अर्थ समझ पाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 71 प्रतिशत बच्चे आधा-चौथाई का अर्थ ही नहीं जानते !

कक्षा नौवीं में टॉप-5 राज्यों के नाम इस प्रकार हैं- पंजाब, केरल, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली। इसी प्रकार बॉटम-5 राज्यों में इन राज्यों के नाम शामिल हैं-उत्तराखंड, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश, गुजरात और उत्तरप्रदेश। इस सर्वे में यह भी पाया गया कि 37 प्रतिशत छात्र ही किशोर अवस्था में वृद्धि, हार्मोनल चेंज और कुल मिलाकर शारीरिक देखभाल के बारे में समझ रखते हैं। अर्थात 63 प्रतिशत छात्र इस उम्र में शारीरिक देखभाल के बारे में कोई जानकारी नहीं रखते हैं। इस कक्षा के 59 प्रतिशत बच्चे आँकड़ों का औसत नहीं बता पाते। इसका मतलब ये भी है कि कक्षा 9वी में 41 प्रतिशत बच्चे ही आँकड़ों का औसत बता पाए।

इस सर्वेक्षण में एक विशेष बात देखने में यह आई कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के गृह राज्य गुजरात कक्षा तीसरी, छठी और कक्षा नौवीं में तीनों स्तरों में एक भी स्तर में टॉप-5 में जगह नहीं बना पाया। बॉटम-5 में जरूर तीनों स्तर में गुजरात ने स्थान प्राप्त किया है। कक्षा तीसरी में गुजरात राज्य बॉटम-5 में सबसे आखिर में देखा गया। कक्षा छठी में बॉटम-5 में गुजरात राज्य चौथे स्थान पर देखा गया। इसी प्रकार कक्षा नौवीं में भी बॉटम 5 में गुजरात ने चौथा स्थान प्राप्त किया है। देश का कोई भी राज्य गुजरात को छोड़कर ऐसा नहीं है जो कक्षा तीसरी, छठी और नौवीं में बॉटम-5 में आया हो। गुजरात राज्य के लिए यह शर्मनाक बात है।

केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय के राष्ट्रीय सर्वेक्षण परख में जो शिक्षा की दयनीय हालत पाई गई, वह दुखद और सोचनीय है। केन्द्र शासन और राज्यों को यह सोचने की आवश्यकता है कि शिक्षा की यह बद्तर हालत क्यों और कैसे हुई ? इसके कारणों की पड़ताल करने की भी सख्त आवश्यकता है। अच्छा होता सर्वेक्षण में उन कारणों की भी खोज-खबर ली होती। शिक्षा की इस दयनीय हालत के लिए मुख्य रूप से कुप्रबंध ही जिम्मेदार है। जहाँ प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले सभी बच्चों के लिए एक मात्र शिक्षक ही तैनात किया जायेगा, तो यह हालत तो होनी ही है। जब बुनियाद ही कमजोर होगी, तो ईमारत बुलंद नहीं बनाई जा सकती। माध्यमिक विद्यालयों में भी पर्याप्त शिक्षक नहीं है।

कहीं-कहीं दो या तीन शिक्षक ही कक्षा पहली से आठवीं तक के बच्चों को पढ़ा रहे है। इसी प्रकार हाई स्कूल में भी विषय विशेषज्ञ नहीं होने से यह देखा गया है कि कला विषय के शिक्षक विज्ञान विषय पढ़ा रहे हैं और विज्ञान विषय का शिक्षक कला विषय पढ़ा रहे हैं। यही नहीं, अनेक ऐसे प्राथमिक विद्यालय हैं, जो भवनविहीन है। वे किसी टापरे में स्कूल लगा रहे है। माध्यमिक विद्यालयों में भी जितने कक्षाओं के मान से कक्ष उपलब्ध होना चाहिए, वे कहीं नहीं है। संसाधनों की अत्यधिक कमी है। शिक्षण सामग्री का स्कूलों में अभाव है। शिक्षक अपने जुगाड़ से शिक्षण सामग्री जुटा पाते हैं।

किस प्रकार प्राथमिक विद्यालय के बच्चे शिक्षा अध्ययन कर रहे है, इसका यहाँ एक उदाहरण देना पर्याप्त होगा। मध्यप्रदेश के गुना जिले के बमौरी विकासखंड के सांगई गाँव में शिक्षा की बदहाली की तस्वीर आपको बता रहे हैं। ग्रामीण ईलाकों के बदहाल स्कूलों की तस्वीरे तो आम है, लेकिन यदि ये पता चले कि शिक्षा विभाग और ग्राम पंचायत ने ही अपने प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के लिए टपरा स्कूल बना दिया है, तो उसे क्या कहेंगे ? यकीन नहीं आता तो सांगई गाँव के एक ऐसे स्कूल पर नजर डाले। यहाँ 3 साल से बच्चे एक टापरे में बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। इस गाँव में सरकारी भवन के नाम पर एकमात्र भवन इसी स्कूल का था, जो पिछले 3 साल से जर्जर अवस्था में है। इसमें खतरे के कारण क्लास नहीं लगाई जा सकती तो विभाग और पंचायत ने इस स्कूल के होनहार नौनिहालों के लिए टपरा स्कूल ही बना दिया !

शिक्षा की बदहाल हालत के लिए केन्द्र सरकार और सभी राज्य सरकारों को गंभीरता पूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। इस बदहाली के कारणों की खोज कर उसे प्राथमिकता पर दूर करने की आवश्यकता है। बच्चों के लिए पर्याप्त स्कूल भवन, शिक्षक और पर्याप्त संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना केन्द्र सरकार और राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता की सूची में आना ही चाहिए। अन्यथा जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा !...

कोई कब जागा तो कोई कब जागा

विचार

राजेंद्र बज

लेखक स्तंभकार हैं।

एकाएक उन्हें इस दिव्यज्ञान की प्राप्ति हुई कि 50 वर्ष पूर्व आपातकाल में जनसाधारण पर तरह-तरह की ज्यादतियां हुई थी। यह आत्मबोध कांग्रेस के अंदरूनी हालात की ओर स्पष्ट रूप से इंगित करता है। वैसे उस दौर में जो तत्काल प्रभाव से जाग गए थे, उन्होंने एकजुट होकर इसे मुद्दा बनाते हुए सत्ता हांसिल कर ली थी। हालांकि कुछ ही समय देशवासियों ने अच्छी तरह समझ लिया कि शासन करना तो केवल और केवल कांग्रेस को ही आता है। नतीजा यह निकला कि आपातकाल के नायक नायिकाओं की सत्ता में वापसी हो गई। खैर, लोकतंत्र है और लोकतंत्र में ऐसा होना अप्रत्याशित भी नहीं कहा जा सकता।

बाद के वर्षों में अलग-अलग राजनीतिक समीकरण बने और नागरिकों ने इस तथ्य को गहराई से जाना कि राजनीतिक बिरादरी में कौन कितना काबिल है? देश पर शासन उन्होंने भी किया और इन्होंने भी किया। जहां तक विपक्षी दल या दलों का सवाल है, तो उसमें तत्कालीन दौर में सत्तापक्ष की गलत नीतियों का सशक्त विरोध करने की गजब की काबिलियत थी। इसके चलते देश में तमाम तरह की लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का क्रियान्वयन बखूबी होता रहा। बीते दौर की राजनीति में शासन करने की क्षमता को लेकर जितना भरोसा कांग्रेस पर था, वह भरोसा अब भाजपा और भाजपानीत संगठन पर जाकर टिक गया है।

यह सब उल्लेख इसलिए भी कि बीते दौर में कांग्रेस को लेकर उसकी जिस क्षमता के नागरिक कायल थे, वह क्षमता आज की कांग्रेस लगभग पूरी तरह से खो चुकी है। एक अरसे से विपक्ष में रहकर भी विपक्षी धर्म का परिपालन करने की दिशा में कांग्रेस कोई अधिक सफल न हो सकी। सीधे तौर पर कहा जाए तो भाजपा ने शासन करना अच्छी तरह से सीख लिया। लेकिन विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस में वह धार नहीं दिखाई दी, जो किसी समय भाजपा की हुआ करती थी। उल्टे कांग्रेस से निकल-निकल कर अनेक दिग्गज भाजपा की भारी भीड़ में सम्मिलित होते गए। अनेक नेताओं को दशकों बाद कांग्रेस में खोट नजर आने लगा।

दरअसल वर्तमान दौर में कांग्रेस की मुख्य कमजोरी कमजोर नेतृत्व की है। आज आम नागरिक के लिए यह समझ पाना मुश्किल है कि आखिर कांग्रेस में सर्वोच्च पद पर कौन आसीन है ? आखिर किसे कांग्रेस का हाईकमान माना जाए ? कांग्रेस की ओर से अंतिम निर्णय लेने का अधिकार आखिर किसके पास है ? क्या कांग्रेस किसी परिवार विशेष की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनकर रह गई है ? क्या कांग्रेस में पद और कद का निर्धारण परिवार विशेष के प्रति समर्पित मनोभाव का परिणाम है ? क्या कांग्रेस में सामूहिक निर्णय लेने की परंपरा है ? और यह सवाल भी कि कांग्रेस आज जिस परिपाटी पर चल रही है, उसका भविष्य क्या है ?

वास्तव में कांग्रेस में रहकर कांग्रेसियों को कोई भविष्य स्पष्ट तौर पर नजर नहीं आता है ? कांग्रेस में तपे तपाए राजनेताओं की भारी कमी दिखाई देती है। अनेक अवसरों पर कांग्रेस की खोखली सोच कांग्रेस को ही शर्मसार कर चुकी है। वैसे अब भी समय है, जबकि कांग्रेस अपने पुराने तेवर में आ सकती है। लेकिन उसे पारिवारिक मोहजाल से बाहर निकल कर कुछ सोचने और कुछ करने की जरूरत है। इसमें कोई दो मत नहीं कि कांग्रेस का अपना अत्यंत गौरवशाली इतिहास रहा है। किसी दौर में देश की एकता और अखंडता के लिए कांग्रेस का अस्तित्व एक मजबूत डोर के रूप में दिखाई देता था। लेकिन आज वह स्थिति नहीं के बराबर है।

कांग्रेस को यह आत्ममंथन करने की भी जरूरत है कि भाजपा से छिटककर कोई कांग्रेस में क्यों नहीं आना चाहता ? भाजपा से दूरी बनाकर चलने वाली शख्सियत अपनी अलग राह क्यों चुन लिया करती है ? एकला चलो रे, का भाव भाजपा विरोधी तबका क्यों आत्मसात करने लगा है ? आखिर कांग्रेस का वह चुंबकीय आकर्षण बोथरा क्यों गया है ? वैसे अब भी समय है जब कांग्रेस अपने पुराने वैभव को पुनः प्राप्त कर सकती है। लेकिन इसके लिए उसे अपने ही दल में आंतरिक लोकतंत्र की स्थापना करना होगी। अन्यथा कांग्रेस का परंपरागत ढांचा छिन्न-भिन्न अवस्था को प्राप्त हो सकता है।

वास्तव में देश के समक्ष वर्तमान सत्तारूढ गठबंधन के सशक्त विकल्प की आवश्यकता लोकतंत्र को अक्षुण्ण रखने के लिए आवश्यक समझी जाती है। हालांकि कांग्रेस कमजोर अवश्य हुई है,लेकिन उसके प्रतिबद्ध मतदाताओं में कहीं कोई कमी नहीं आई है। बेशक संख्याबल के लिहाज से वह सत्ता से बहुत दूर है। लेकिन इस समय देश में जो वातावरण बनता दिखाई देता है, उसके संदर्भ में उसे आम नागरिकों के समक्ष स्वयं को सशक्त विकल्प के रूप में दिखाई देने की जरूरत है। लेकिन ऐसा तब ही हो सकता है जबकि कांग्रेस पर एकल नियंत्रण की अपेक्षा सामूहिक प्रबंधन पर विशेष रूप से गौर किया जाए।

स्वामी, सुबह सवेरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक उमेश त्रिवेदी द्वारा श्री सिद्धीविनायक प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 26-बी, देशबंधु परिसर, प्रेस कॉम्पलेक्स, जोन-1, एम.पी.नगर, भोपाल, म.प्र. से मुद्रित एवं डी-100/46, शिवाजी नगर भोपाल से प्रकाशित।

प्रधान संपादक
उमेश त्रिवेदी
कार्यकारी प्रधान संपादक
अजय बोकिल
संपादक (मध्यप्रदेश)
विनोद तिवारी
वरिष्ठ संपादक
पंकज शुक्ला
प्रबंध संपादक
अरुण पटेल
(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल रहेगा)
RNI No. MPHIN/ 2003/ 10923,
Ph. No. 0755-2422692, 4059111
Email- subahsaverenews@gmail.com

'सुबह सवेरे' में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं। इनसे समाचार पत्र का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

जीवन पर प्रकाश डालिए

व्यंग्य

प्रदीप औदिच्य

लेखक व्यंग्यकार हैं।

आंखें तब ही देख पाती है जब प्रकाश हो इसका अर्थ ये है कि आंखें मंत्री है और प्रकाश उनका पी ए। प्रकाश जिधर दिखाता है उधर ही आंखे देखती है ।जीवन के लिए प्रकाश होना और जीवन पर प्रकाश डालना दोनों लगभग एक जैसे काम है। जीवन पर प्रकाश डालने से तो कई बार वह बातें चमकदार हो जाती है जो अंधेरे में होती हैं। इस बात पर कोई कहानी कही जाए तो वो ऐसी होगी। देश में नगर होते है, सभी नगर में होता है एक नगर सेठ ।इस नगर सेठजी के पिताजी सेठ नहीं थे ।लेकिन, ये किसी कारण बस हो गए थे। अब हुए ही थे कि उनको लगा ,क्या सेठ भर हो जाने से कुछ होता है ? सेठ तो इस कारण से हो हुए कि सेठ जी का धन का उन रास्तों से आता था जो कानून की किताब और जेल की अंधेरी कोठरी में जाते थे। लेकिन धन प्रकाश उस रास्ते को प्रकाशित करता था कि सेठजी उसमें कभी फंस ही नहीं पाए। सेठजी की दुकान से चौराहे के होर्डिंग दिख रहे थे।वह एक दिन सोचने लगे कि मेरा जीवन क्या बिना होर्डिंग, बिना अखबार के विज्ञापन के बीत जाएगा ? मेरे परिवार का नाम किसी मंदिर के पत्थर पर दिखे या न दिखे चौराहे पर जरूर दिखना चाहिए। धत..क्या फायदा ऐसे धन का जो किसी होर्डिंग वाले के काम न आए। बेकार है, वह धन जो चेहरे को कई अखबारों के कोने की शोभा न बढ़ाए। सेठजी ने ठान लिया कि वह अब इस उम्र में वही सब करेंगे जो गणमान्य नागरिक का दर्जा दिलाए। वह समाज सेवी बनके रहेंगे।

मुनीम ने कहा सेठ जी,ये बड़ी बात नहीं है,अब समाज सेवी बनना बहुत आसान है ।उसके लिए आपको किसी की सेवा का करने की जरूरत नहीं है बस आप स्वयं के पैसे से खुद के लिए ये उपाधि प्राप्त कर सकते हो।करना क्या है ? सेठ जी ने पूछा । मुनीम ने कहा सब जगह लिखना है समाज सेवी ,बस हो गए समाज सेवी न समाज पूछता है कि सेवा कहां है ? न सेवा पूछती है कि कौन से समाज की करनी है । अब सेठजी ने कहा हम अपना जन्मदिन मनाएंगे ।जन्मदिन पर टेंट लगाया गया माइक, माला,फोटोग्राफर सब तैयार थे ।प्रयास से लोग लाए गए। फोटोग्राफर के सामने गाय को चारा डाला गया।ये वही गाय थी जिसके रोज दुकान पर आने पर चार डंडे पड़ते थे,चूंकि आज सेठ जी जन्मदिन पर लंबी आयु का वरदान पाना चाहते थे ।इसके लिए बीस रुपए का चारा डाला गया। गाय ने चारा मुंह में रखा ,फिर थूक दिया । गाय भी जानती थी कि सेठ की लंबी उम्र मतलब हमारा रोज डंडे खाना ।

गाय खाए न खाए फोटो में सेठजी, गाय और चारा दिखाई दे गया, बस लग गया जुगाड समाजसेवी होने का। इधर सेठजी के दुकान मंच थी और माइक भी। अब सेठ जी को महान बताने के लिए वक्ता चाहिए।संचालक ने घोषणा कर डाली सेठ जी के जीवन पर प्रकाश डालने के लिए मास्टर साहब आयेंगे मास्टर साहब रिटायर्ड थे,उन्होंने प्रकाश डाला 'ये भरोसा.. मतलब सेठ राम भरोसा जी के जीवन पर प्रकाश डालने के लिए मै यहां आया हूं ।

अब राम भरोसे को भरोसा तो राम पर नहीं है ,ये भरोसा बस पैसे पर करते है। इनके जीवन पर जब प्रकाश डालते है तो कई तरह की रंगीनियां निकलती है मतलब रंगीन रोशनी जीवन में थी। मास्टर साहब ने गला खंगाला और फिर आगे बोले इनके घर इतने रोशन हुए कि इन्होंने कभी बिजली का बिल ही नहीं भरा । इसका मतलब ये नहीं कि बिजली का नहीं थी बल्कि ये सीधे खंभे से तार जुड़े हुए थे । ये कभी मंदिर नहीं गए क्यों कि मंदिर की दो दुकानों पर कब्जा था ,मंदिर वाले घुसने ही नहीं देते थे।सेठ जी बहुत दयालु है,गरीबों के चिन्तक है ,उनको गरीब की सुरक्षा की चिंता रहती है, उनके घर से गहने चोरी न चले जाएं इसलिए गरीब के जेवरात वापिस नहीं किए। सेठजी ने इशारा किया मास्टरजी से माइक लिया।मुनीम ने कहा अब ज्यादा प्रकाश ठीक नहीं है,आप सब लोग भोजन कीजिए।

दृष्टिकोण

लोकेन्द्र सिंह

लेखक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापक हैं।

अमर्यादित नहीं हो सकती है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता

सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसी ही अमर्यादित अभिव्यक्ति के मामलों की सुनवाई के दौरान बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं, जिन पर हमें गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था की रीढ़ है। इस पर किसी प्रकार के बाहरी प्रतिबंध लगाना उचित नहीं होगा। लेकिन यदि इसी प्रकार अमर्यादित लिखा-पढ़ी, बयानबाजी और कार्टूनबाजी जारी रही तब समाज में वैमनस्य और सांप्रदायिक तनाव को फैलने से रोकने के लिए कुछ न कुछ युक्तियुक्त प्रबंध करने ही पड़ेंगे। सोशल मीडिया के इस दौर में किसी को भी अमर्यादित और असीमित अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती है। नागरिकों को भी समझना चाहिए कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की एक मर्यादा है, उसे लांघना किसी के भी हित में नहीं है। उचित होगा कि नागरिक समाज इस दिशा में गंभीरता से चिंतन करे।

जब हम विरोध, आलोचना और असहमति के वास्तविक स्वरूप को भूलते हैं तब हमारी अभिव्यक्ति घृणा और नफरत में बदल जाती है। मौजूदा समय में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और राष्ट्रीय विचार के संगठनों एवं कार्यकर्ताओं पर टिप्पणी का स्वर ऐसा ही दिखायी पड़ रहा है, जो अमर्यादित है। सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसी ही अमर्यादित अभिव्यक्ति के मामलों की सुनवाई के दौरान बहुत महत्वपूर्ण बातें कहीं है, जिन पर हमें गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था की रीढ़ है। इस पर किसी प्रकार के बाहरी प्रतिबंध लगाना उचित नहीं होगा। लेकिन यदि इसी प्रकार अमर्यादित लिखा-पढ़ी, बयानबाजी और कार्टूनबाजी जारी रही तब समाज में वैमनस्य और सांप्रदायिक तनाव को फैलने से रोकने के लिए कुछ न कुछ युक्तियुक्त प्रबंध करने ही पड़ेंगे। सोशल मीडिया के इस दौर में किसी को भी अमर्यादित और असीमित अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती है। नागरिकों को भी समझना चाहिए कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की एक मर्यादा है, उसे लांघना किसी के भी हित में नहीं है। उचित होगा कि नागरिक समाज इस दिशा में गंभीरता से चिंतन करे। सर्वोच्च न्यायालय ने उचित ही कहा है कि 'अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का गलत इस्तेमाल समाज में नफरत और विघटन को जन्म दे सकता है। इसलिए नागरिकों को चाहिए कि वे जिम्मेदारी से बोलें, संयम रखें और दूसरों की भावनाओं का सम्मान करें'।

हमारे यहाँ तो महापुरुषों ने भी कहा है कि जो व्यवहार हम अपने लिए अपेक्षित करते हैं, वही व्यवहार हमें सामने वाले के साथ करना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ के सामने आया वजाहत खान का मामला ऐसा ही है, जिसमें हिन्दू देवी पर तो आपत्तिजनक पोस्ट कर रहा है लेकिन इस्लाम के बारे में आपत्तिजनक पोस्ट करने वालों के विरुद्ध शिकायत दर्ज करा है। जब पलटकर किसी ने हिन्दू धर्म का अपमान करने के आरोप में उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी, तो वह न्यायालय में पहुँच गया है। याद हो कि सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनौली ने ऑपरेशन सिंदूर के समय भावावेश में आकर कोई आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। हालांकि जब उसे अपनी गलती का अहसास हुआ तो उसने बिना शर्त माफी भी माँग ली और अपना वह वीडियो भी हटा लिया था। लेकिन इसके बावजूद वजाहत खान ने उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी थी। हालांकि ऐसा करते समय वजाहत खान ने अपने गिरेबां में झांककर नहीं देखा कि वह क्या कर रहा है? जब आप अपनी आस्था पर कोई आपत्तिजनक टिप्पणी सुनना पसंद नहीं करते तब आपको दूसरों के देवी-देवताओं पर अभद्र टिप्पणियां करने का अधिकार किसने दे दिया है? अच्छा ही हुआ कि वजाहत खान जैसों को आईना दिखाने के लिए हिन्दू देवी-देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणियां करने पर उनके विरुद्ध भी प्रकरण दर्ज करा दिया गया है। अब उन्हें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मोल समझ आएगा। न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा है कि 'लोगों को हेट स्पीच क्यों अटपटे और गलत नहीं लगते हैं। ऐसे कंटेंट पर नियंत्रण होना चाहिए। साथ ही लोगों को भी ऐसे नफरत भरे कंटेंट को शेयर करने और लाइक करने से बचना चाहिए'।

इसी प्रकार, सर्वोच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की पीठ ने इंदौर के कार्टूनिस्ट हेमंत मालवीय के बेहद आपत्तिजनक कार्टून को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए सख्त टिप्पणी की है। न्यायालय ने कार्टूनिस्ट की मानसिकता पर प्रश्न उठाया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर बनाए गए इस आपत्तिजनक कार्टून को लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि 'आजकल कार्टूनिस्ट और स्टैंडअप कॉमेडियन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर रहे हैं। क्या ये लोग कुछ भी बनाने और बोलने से पहले सोचते नहीं है?' न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि 'अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर इस प्रकार के घृणित व्यंग्य चित्रों को संरक्षण नहीं दिया जा सकता है। हेमंत मालवीय के कार्टून में कोई परिपक्वता नहीं है। ये वास्तव में भड़काऊ है'। याद हो कि इस कार्टूनिस्ट के मामले में मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय भी फटकार लगा चुका है। उच्च न्यायालय ने जब कार्टूनिस्ट की जमानत याचिका खारिज की तो उसने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था लेकिन यहाँ भी उनके कृत्य पर कोई राहत नहीं मिली है। हेमंत मालवीय के कार्टून में कोई कलात्मक अभिव्यक्ति भी नहीं है। अपनी वैचारिक और राजनीतिक खुन्नस निकालने के लिए इस प्रकार के लोग कला को भी बदनाम करते हैं, जो अभिव्यक्ति की सशक्त माध्यम हैं। मजेदार तथ्य यह कि हेमंत मालवीय का बचाव कर रहे उनका भी वकील यह मानता है कि 'हाँ, ये घटिया कार्टून है। लेकिन क्या ये अपराध है? नहीं, यह अपराध नहीं हो सकता। यह आपत्तिजनक हो सकता है लेकिन अपराध नहीं'। अब यह अपराध है या नहीं, यह तो न्यायालय तय करेगा लेकिन मालवीय का वकील कम से कम यह तो स्वीकार ही कर रहा है कि कार्टून घटिया है। आरोप यह हैं कि उनका कार्टून प्रधानमंत्री और एक राष्ट्रीय संगठन का अपमान ही नहीं करता है अपितु सांप्रदायिकता को भी भड़काता है। हेमंत मालवीय की शिकायत दर्ज करानेवाले सामाजिक कार्यकर्ता विनय जोशी आरोप लगाए हैं कि 'मालवीय ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक सामग्री अपलोड करके हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाई और सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ा'। उनकी ओर से दर्ज करायी गई एफआईआर में कई 'आपत्तिजनक' पोस्ट का उल्लेख किया गया है, जिनमें भगवान शिव पर कथित रूप से अनुचित टिप्पणियों के साथ-साथ मोदी, आरएसएस कार्यकर्ताओं और अन्य लोगों के बारे में कार्टून, वीडियो, तस्वीरें और टिप्पणियाँ शामिल हैं। इससे स्पष्ट होता है कि हेमंत मालवीय ने पहली बार आपत्तिजनक कार्टून नहीं बनाया था, बल्कि यह उनका नियमित अभ्यास है। न्यायालय के अनुसार, इस प्रकार की प्रवृत्तियों को रोका जाना अत्यंत आवश्यक है।

बहरहाल, सर्वोच्च न्यायालय की इस सलाह पर नागरिक समाज को न केवल चिंतन-मनन करना चाहिए अपितु उसका अनुकरण भी करना चाहिए- 'नागरिकों को अपनी बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी की कीमत समझनी चाहिए और इसके साथ-साथ स्व-नियंत्रण और संयम का पालन करना चाहिए'। सर्वोच्च न्यायालय ने तो यह भी कहा है कि सोशल मीडिया पर बढ़ती विभाजनकारी प्रवृत्तियों पर रोक लगाई जानी चाहिए। न्यायालय ने केन्द्र और राज्य सरकारों को कहा है कि वे नफरत फैलाने वाले भाषणों को रोकें। हालांकि न्यायालय ने किसी भी प्रकार की सेंसरशिप की बात से इनकार किया। यानी नागरिकों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बाधित नहीं होनी चाहिए। इसके लिए न्यायालय ने वकीलों एवं सरकारों से सुझाव भी माँगे हैं। हालांकि यह राह बहुत कठिन है कि सरकार किसी प्रकार का प्रतिबंध भी न लगाए और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर नफरती सोच पर लगाम भी लगा ले। इस दिशा में यदि कहीं कोई राह दिखायी देती है, तो वह जागरूक नागरिक समाज है। समाज को ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दुरुपयोग को रोकने के लिए आगे आना होगा। जब नफरती भाषण करनेवालों को प्रोत्साहित करने की अपेक्षा हतोत्साहित किया जाने लगेगा, तब बहुत हद तक इस पर नियंत्रण हो जाएगा। यहाँ राष्ट्रीय विचार के कार्यकर्ताओं के धैर्य की सराहना करनी होगी कि वे नफरत की बौछारों को अनदेखा करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। जबकि अन्य विचार या संप्रदाय के प्रति अमर्यादित बयानबाजी होती है, तो तत्काल उग्र प्रतिक्रिया देखने को मिलती है। शायद इसलिए ही सबने हिन्दू धर्म, हिन्दू संगठन और हिन्दू समाज को पंचिंग बैग समझ लिया है। इस पर लगाम लगनी ही चाहिए। बहरहाल, सर्वोच्च न्यायालय के इस आग्रह का पालन व्यापक स्तर पर हम सबको करना चाहिए, जिसमें न्यायालय ने कहा कि 'लोग स्वयं से जिम्मेदारी निभाएं और अपनी बातों में संयम बरतें।'

बेटी भ्रूण हत्या: आँकड़े नहीं, संवेदना की चीख

हरियाणा

प्रियंका सौरभ

लेखक शोधार्थी हैं।

जिस धरती पर दुर्गा, सरस्वती और लक्ष्मी जैसी नारियों की पूजा होती है, उसी धरती पर बेटियाँ आज भी माँ की कोख में दम तोड़ रही हैं। हाल ही में आई एक रिपोर्ट ने हरियाणा की उस कड़वी सच्चाई को फिर से उजागर किया है, जिसमें तीन महीनों में एक हज़ार एक सौ चौवन गर्भपात दर्ज किए गए – जिनमें अधिकांश के पीछे पुत्री होने की संभावना प्रमुख कारण मानी जा रही है।

यह आँकड़ा केवल एक संख्या नहीं, बल्कि हमारे समाज के भीतर छुपी पुरुषप्रधान सोच, भेदभावपूर्ण मानसिकता और शासन-प्रशासन की विफलता का प्रत्यक्ष प्रमाण है।

सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को जमीनी स्तर तक पहुँचाने के लिए आशा कार्यकर्ताओं को 'सहेली' की भूमिका में तैनात किया था। उनका कर्तव्य था कि वे गर्भवती महिलाओं की नियमित निगरानी करें, उनके स्वास्थ्य की देखरेख करें, और सही सलाह देकर उन्हें सहयोग प्रदान करें। किन्तु छप्पन आशा कार्यकर्ताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाना यह दर्शाता है कि इस निगरानी प्रणाली में गम्भीर लापरवाही हुई है।

क्या ये कार्यकर्ता जानबूझकर लापरवाह थीं, या उनके पास संसाधनों की कमी थी? क्या वे सामाजिक दबाव, भय अथवा अव्यवस्था के कारण चुप रहीं? यह गहन जाँच का विषय है, क्योंकि केवल दंड देना समाधान नहीं, अपितु इस समस्या का संवेदनशील समाधान आवश्यक है।

हमारे देश में गर्भधारण से पूर्व एवं पूर्व प्रसव भ्रूण परीक्षण निषेध अधिनियम के अंतर्गत भ्रूण की लिंग जाँच तथा लिंग के आधार पर गर्भपात एक दंडनीय अपराध है। परंतु यह अधिनियम केवल कागज़ों तक सीमित रह गया है।

हरियाणा में कई स्थानों पर अवैध भ्रूण परीक्षण केंद्र, निजी चिकित्सा केंद्रों की मिलीभगत, तथा पैसे के लालच में लिंग जाँच और भ्रूण हत्या आज भी बेरोक-टोक जारी है। इन केंद्रों पर रोक लगाने हेतु बनाए गए विशेष दस्तों तथा निरीक्षण टीमों की सक्रियता केवल औपचारिकता बनकर रह गई है।

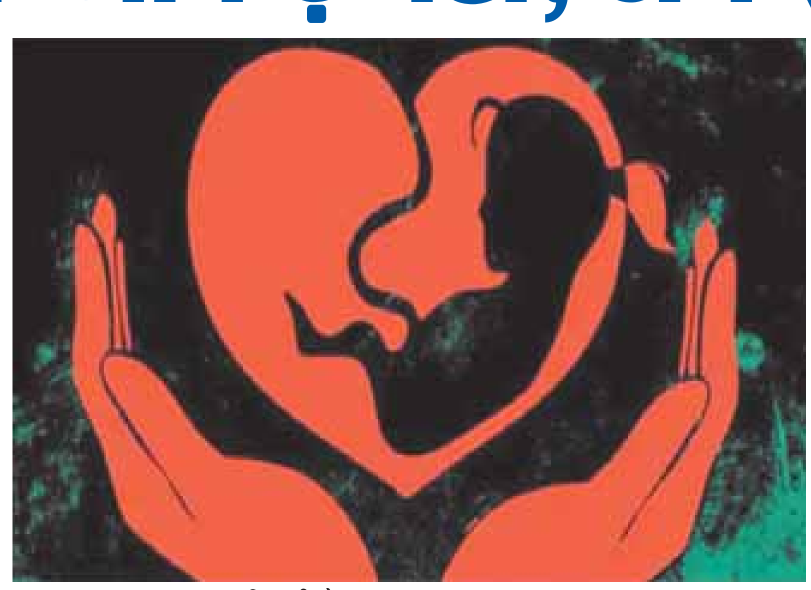

स्वास्थ्य विभाग ने गर्भपात करवाने वाली महिलाओं की 'पश्च परीक्षण प्रणाली' को अधिक कठोर करने की घोषणा की है तथा विशेष रूप से उन महिलाओं की निगरानी बढ़ाने की बात कही है, जिनकी पहले से एक या अधिक पुत्रियाँ हैं। उद्देश्य सकारात्मक है, परंतु यदि इसे संवेदनशीलता और सम्मान के साथ लागू नहीं किया गया, तो यह कदम स्वयं महिलाओं के स्वास्थ्य अधिकारों और निजता पर प्रहार बन सकता है।

क्या यह निगरानी केवल भय का वातावरण उत्पन्न करने का माध्यम बन रही है? या फिर वे महिलाएँ, जो सामाजिक दबाव में आकर गर्भपात करवाने को विवश हुईं, अब एक बार फिर पीड़िता की बजाय अपराधिनी बना दी जाएँगी?

'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' जैसे नारे केवल दीवारों पर लिखे जा रहे हैं अथवा नेताओं के भाषणों में दोहराए जा रहे हैं। ज़मीनी सच्चाई यह है कि ग्रामीण ही नहीं, शहरी समाज भी पुत्री को आज भी एक बोझ के रूप में देखता है। दहेज, सुरक्षा, सम्मान और वंश परंपरा जैसे कुप्रथाओं के कारण बेटियाँ आज भी अवांछित हैं।

क्या केवल नारेबाज़ी पर्याप्त है या इस दिशा में मूलभूत सामाजिक परिवर्तन की आवश्यकता है?

कोख में हो रही बेटियों की हत्या केवल माँ या परिवार की जिम्मेदारी नहीं है। यह एक सामूहिक अपराध है, जिसमें समाज, चिकित्सा संस्थान, प्रशासनिक व्यवस्था और हम सब शामिल हैं।

जब कोई महिला दूसरी या तीसरी बार पुत्री को जन्म देने वाली होती है, तो समाज उसकी मानसिकता, पात्रता और पारिवारिक स्थिति पर कटाक्ष करता है। यही मानसिकता उस माँ को मजबूर करती है कि वह अगली बार कन्या का जन्म न होने दे – भले ही इसकी क़ीमत किसी जीवन के रूप में क्यों न हो।

केवल नोटिस, निलंबन और निगरानी से यह विकराल समस्या नहीं सुलझेगी। इसके लिए आवश्यक है - स्थानीय स्तर पर महिला सशक्तिकरण अभियान, पुत्रियों के जन्म पर प्रोत्साहन योजनाओं का क्रियान्वयन, जनजागृति के लिए पत्र-पत्रिकाओं, चलचित्रों और सामाजिक माध्यमों का उपयोग, पारिवारिक मुखियों को संवेदनशील बनाना, लिंग परीक्षण करने वाले चिकित्सकों पर कठोर दंडात्मक कार्यवाही, अवैध भ्रूण परीक्षण केंद्रों को बंद करना, तथा शैक्षणिक पाठ्यक्रमों में लिंग समानता की शिक्षा को समाविष्ट करना।

आशा कार्यकर्ताओं को दंडित करना एक सतही समाधान है। असल प्रश्न यह है – क्या उन्हें आवश्यक प्रशिक्षण, संसाधन, समय पर मानदेय तथा कार्यस्थल पर सुरक्षा प्राप्त थी? जिन चिकित्सकों ने अवैध लिंग जाँच की, जिन केंद्रों ने भ्रूण हत्या करवाई, तथा जिन परिवारों ने कन्या को अस्वीकार किया – क्या उन सबको भी समान रूप से उत्तरदायी ठहराया गया?

यदि माताओं को निर्णय लेने का अधिकार देना है, तो उन्हें शिक्षा, आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक सम्मान देना होगा। बेटी तभी बचेगी जब उसकी जननी स्वयं को सक्षम और सशक्त मानेगी। आज आवश्यकता है कि हम हर माँ को यह कहें – 'तू दुर्बल नहीं है, तेरे गर्भ में एक शक्ति पल रही है।'

पश्च परीक्षण प्रणाली और पुलिसिया दबाव केवल भय का वातावरण उत्पन्न करेंगे। इनकी अपेक्षा यदि हम संवाद को प्राथमिकता दें, महिलाओं को उनके अधिकारों की जानकारी दें, तथा समाज में बेटियों के लिए सम्मान का भाव विकसित करें – तो परिणाम अधिक स्थायी और सकारात्मक होंगे।

एक हज़ार एक सौ चौवन गर्भपात केवल आँकड़े नहीं हैं। ये उस सामूहिक हत्या की पटकथा हैं, जो केवल इसीलिए लिखी गई क्योंकि भ्रूण स्त्रीलिंग का था। यह केवल हरियाणा नहीं, सम्पूर्ण भारत की नैतिक हार है। जब तक हम लिंग के आधार पर भेदभाव करते रहेंगे, तब तक कोई नीति, कोई योजना, कोई निगरानी प्रणाली प्रभावी सिद्ध नहीं होगी।

मुद्दा

आर. बी. त्रिपाठी

लेखक स्तंभकार हैं।

सिक्योरिटी गार्ड, प्रवेश द्वार पर बीतती जिंदगी

दायित्व सुरक्षा का। चोर डकैतों, असामाजिक तत्वों से घरों, कॉलोनियों, मॉल, कवर्ड कैम्पस, संस्थानों, उद्योगों की सुरक्षा करना, अनाधिकृत प्रवेश को रोकना, आने- जाने वाले वाहनों को रोककर पूछताछ करना,कवर्ड कैम्पस आदि में रजिस्टर संधारित करना। इसके लिये ड्यूटी पर सदैव चौकन्ने होकर सतर्क निगाह रखना। जरा भी चूक हुई नहीं कि संबंधित संस्थान द्वारा उनकी अच्छे से खबर ली जाने का भय हमेशा बना रहता है। सिक्योरिटी एजेंसी के संचालकों द्वारा पड़ने वाली डांट फटकार अलग से।

एक ऐसे वक्त जब देश की सीमाओं पर हमारे बहादुर सैनिक दिन रात चौकसी रख रहे हैं तब आंतरिक सुरक्षा के काम में सुरक्षा गार्ड्स का योगदान भी कम नहीं आंका जा सकता। हमारे यहां जनसंख्या के अनुपात में पुलिस कर्मियों की संख्या बहुत कम है। ऐसे में रहवासी इलाकों, बड़े प्रतिष्ठानों, शॉपिंग मॉल, कवर्ड कैम्पस, बड़े ज्वेलर्स आदि में सुरक्षा की दृष्टि से सिक्योरिटी गार्ड की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। लेकिन इस काम के बदले उन्हें मिलने वाली पगार वर्तमान महंगाई के दौर में बहुत कम प्रतीत होती है।

उन्हें 'सिक्योरिटी गार्ड' के नाम से पुकारा जाता है। मौसम कैसा भी हो सर्दी, गर्मी या बारिश वे अपनी ड्यूटी पर तैनात रहते हैं। हाथों में सिर्फ एक छोटा सा डंडा, टार्च और मोबाइल लिये ही उन्हें निहत्थे ही सुरक्षा का भार सौंप दिया जाता है। दस से बारह घंटे की लगातार ड्यूटी के लिये महज दस से बारह हजार रुपये मासिक पर इस काम में कई युवा, युवतियां, अधेड़ उम्र वाले तथा कुछ उम्रदराज लोग भी देखे जा सकते हैं। बैंक, वित्तीय संस्थानों, बड़े ज्वेलर्स और संवेदनशील स्थानों पर उनके हाथों में गन रहती है लेकिन इसके बावजूद बैंकों आदि में लूटपाट की घटनाएं सुर्खियां बटोरती रहती है। हालांकि ऐसे प्रतिष्ठानों में रिटायर्ड सैनिकों या रिटायर्ड पुलिस कर्मियों को गार्ड के बतौर रखा जाता है।

दायित्व सुरक्षा का। चोर डकैतों, असामाजिक तत्वों से घरों, कॉलोनियों, मॉल, कवर्ड कैम्पस, संस्थानों, उद्योगों की सुरक्षा करना, अनाधिकृत प्रवेश को रोकना, आने- जाने वाले वाहनों को रोककर पूछताछ करना,कवर्ड कैम्पस आदि में रजिस्टर संधारित करना। इसके लिये ड्यूटी पर सदैव चौकन्ने होकर सतर्क निगाह रखना। जरा भी चूक हुई नहीं कि संबंधित संस्थान द्वारा उनकी अच्छे से खबर ली जाने का भय हमेशा बना रहता है। सिक्योरिटी एजेन्सी के संचालकों द्वारा पड़ने वाली डांट फटकार अलग से।

सिक्योरिटी गार्ड के लिये जरूरी ट्रेनिंग तथा प्लेसमेंट के लिये अनेक प्रायवेट एजेंसियां, संस्थाएं काम कर रही है। ये संस्थाएं मांग पर संबंधित को गार्ड उपलब्ध कराती है। उन्हें अपनी निर्धारित वर्दी दी जाती है लेकिन कथित तौर पर इसके लिये भी गार्ड से राशि काट ली जाती है। विडंबना यह है कि गार्ड को दस से बारह हजार रुपये मासिक ही दिया जाता है। कुछ अपवादों को छोड़कर इनका पीएफ काटा जाता है। बेरोजगारी के इस दौर में इसके बावजूद अनेक लोग इस काम में लगे हैं। सोचें, इतनी महंगाई में ये लोग कैसे अपने परिवार का भरण-पोषण करते होंगे।

विश्व बैंक की महत्वाकांक्षी डीपीआईपी परियोजना में काम करते समय हमें कुछ जिलों में सिक्योरिटी गार्ड के चयन, ट्रेनिंग आदि का काम देखने का मौका मिला था। इस कार्यक्रम में उस दौरान कई जरूरतमंद लोगों को रोजगार सुलभ हुआ था। इस मुहिम का उद्देश्य भी गांव के इच्छुक युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना था। मुझे स्मरण आता है कि रीवा जिले में इस दिशा में उल्लेखनीय कार्य हुआ था।

सिक्योरिटी गार्ड के काम में लगे लोगों में से हमने दर्जन भर से अधिक गार्ड से बातचीत की। इंदौर के एक कवर्ड कैम्पस में गार्ड अमर सिंह (आग्रह पर परिवर्तित नाम) से काफी कुछ जानने का मौका मिला। उनके हाथ में लाठी, टार्च और छोटा सा मोबाइल रहता है तथा वे बड़ी स्टाइल से खड़े रहते हैं। उनका कहना था कि जो कुछ मिलता है उससे इंदौर जैसे शहर में पूरा नहीं पड़ता लेकिन परिवार के लिये थोड़ा-बहुत कुछ तो कर पाते हैं। स्वभाव से वे मस्त मौला लगे। इसी कैम्पस में शाजापुर से आकर गार्ड का काम कर रहे शांतिलाल बताते हैं कि इस काम में पैसा कम मिलता है लेकिन क्या करें। एक अन्य रहवासी इलाके की सुरक्षा के लिये तैनात युवक वीरेन्द्र की कुछ समय पूर्व ही शादी हुई। परिवार की जिम्मेदारी आते ही उन्हें सिक्योरिटी गार्ड बनना पड़ा। इतनी जल्दी कोई दूसरा जॉब नहीं मिल सकता था।

इधर भोपाल के एक मॉल में सागर से आकर गार्ड का काम कर रही युवती ने बताया कि आज के समय घर-परिवार चलाने के लिये पति पत्नी दोनों को कमाई करना जरूरी है। उनके पति भोपाल में ही किसी ओर जगह गार्ड हैं। भोपाल के दस नंबर मार्केट स्थित सौन्दर्य प्रसाधन और आधुनिक पहनावे की बड़ी शॉप पर सिक्योरिटी गार्ड विदिशा से रोजाना आना जाना करते हैं क्योंकि बड़े शहर में इतने पैसों में काम चल नहीं पाता। लेकिन छोटी जगह काम धंधा नहीं होने से शहर आना पड़ता है। सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहे ऐसे कई लोग आपको अन्य जगहों पर भी मिल जायेंगे लेकिन सबकी व्यथा कथा कहिये या कहानी मिलती जुलती ही होती है।

इस काम में जोखिम भी कम नहीं है। हाल ही में इंदौर में एक कवर्ड कैम्पस में रात के समय चोरों ने धावा बोलकर गार्ड को कमरे में बंद कर सूने घर में चोरी वारदात की। इंदौर में ही एक गार्ड की गन चोरी चली गई तो एक अन्य गार्ड को ड्यूटी से लौटते वक्त अज्ञात वाहन ने कुचल दिया। कई मामलों में गार्ड के साथ मारपीट कर उन्हें चोट पहुंचाना आये दिन चलता रहता है। इसके बावजूद इस काम में अनेक जरुरतमंदों को रोज़गार मिल रहा है यह भी सच है।

9 साल पहले तत्कालीन मंत्री के निर्देश पर बने आंचल कक्ष बदहाल

कहीं दरवाजे टूटे, तो कहीं आंचल कक्ष में रखा है कबाड़ का सामान

बैतूल। महिलाएं अपने बच्चों को स्तनपान करवा सकें, इसके लिए आंचल कक्ष बनाये गये थे। लेकिन महिलाओं की सुविधा के लिए बनाए गए आंचल कक्षों की स्थिति सही न होने से महिलाओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल 9 साल पहले प्रदेश की तत्कालीन महिला व बाल विकास मंत्री अर्चना चिटनीस के निर्देश पर महिला एवं बाल विकास विभाग ने सुरक्षित मातृत्व एवं सार्वजनिक स्थल पर महिलाओं को अपने बच्चों को स्तनपान कराने के लिए जिला मुख्यालय के कलेक्ट्रेट, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, वन स्टाप सेंटर सहित मुलताई के बस स्टैंड पर आंचल कक्ष बनवाए थे। विभाग ने एक आंचल कक्ष को बनाने में 8 से 10 हजार रुपए खर्च किए थे। लेकिन देखरेख के अभाव में अब यह आंचल कक्ष पूरी तरह कबाड़ में तब्दील हो गये है। आंचल कक्ष का बोर्ड नदारद है। दरवाजा टूट गया है। महिलाएं इसमें जाने में भी संकोच करती हैं। अंदर आसपास के दुकानदारों का सामान रखा हुआ है। जिसकी वजह से बच्चों को स्तनपान कराने में महिलाओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

कहीं दरवाजे टूटे, तो कहीं कक्ष में रखा है सामान

जिला मुख्यालय पर सार्वजनिक स्थानों पर आंचल कक्ष बनाये गये थे। लेकिन इन आंचल कक्षों की हालत अब बदतर हो गई है। बस स्टैंड पर बना आंचल कक्ष का दरवाजा टूटा है, अंदर दुकान का सामान भरा पड़ा है। बोर्ड भी नदारद है। इससे महिलाओं को आंचल कक्ष की जानकारी नहीं होने से वे बच्चों को स्तनपान के लिए जगह ढूंढती रहती हैं। कलेक्ट्रेट कार्यालय में आंचल कक्ष का बोर्ड लगा हुआ है। अंदर महिलाओं के बैठने के लिए बेंच रखी है। कक्ष में दरवाजा और पर्दे लगे हुए हैं। लेकिन अंदर सामान रखे होने के कारण महिलाएं यहां पर नहीं जाती हैं और महिलाएं बच्चों को स्तनपान करवाने के लिए जगह तलाशती हैं।

8 से 10 हजार रुपये किये थे खर्च

विभाग ने सार्वजनिक स्थानों पर आंचल कक्ष बनाने के लिए 8 से 10 हजार रुपये खर्च किये थे। 9 साल पहले प्रदेश की तत्कालीन महिला व बाल विकास मंत्री अर्चना चिटनीस के निर्देश पर महिला एवं बाल विकास विभाग ने सुरक्षित मातृत्व एवं सार्वजनिक स्थल पर महिलाओं को अपने बच्चों को स्तनपान कराने के लिए जिला मुख्यालय के कलेक्ट्रेट, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, वन स्टाप सेंटर सहित मुलताई के बस स्टैंड पर आंचल कक्ष बनवाए थे। लेकिन अब यह आंचल कक्ष केवल नाममात्र के रह गये है। कहीं कबाड़ भरा है, तो कहीं आंचल कक्ष का बोर्ड ही नजर नहीं आता है। जिससे महिलाओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

इनका कहना है –

तत्कालीन महिला व बाल विकास मंत्री के निर्देश पर आंचल कक्ष बनाए गए थे। सार्वजनिक स्थानों पर बने आंचल कक्षों के सुधार और रखरखाव के संबंध में नगरपालिका से चर्चा की जायेगी। जहां भी कक्षों की मरम्मत की जरूरत है, उसके लिए प्रयास किए जाएंगे, और उन्हें बेहतर किया जाएगा।

– **गौतम अधिकारी,** जिला परियोजना अधिकारी, महिला व बाल विकास विभाग, बैतूल

बदहाली के लिए विभागीय अनदेखी बड़ा कारण

महिला एवं बाल विकास विभाग ने सुरक्षित मातृत्व एवं महिलाओं को अपने बच्चों को स्तनपान कराने के लिए सार्वजनिक स्थल पर आंचल कक्ष बनाये थे। लेकिन यह आंचल कक्ष विभागीय लापरवाही की भेंट चढ़ गए हैं। हालात यह है कि अधिकांश आंचल कक्ष अब खत्म हो गए हैं और जो बचे हैं, वहां पर कबाड़ और दुकान का सामान भरा पड़ा है। ऐसे में महिलाओं को बच्चों को स्तनपान करवाने के लिए महफूज जगह की तलाश करना पड़ता है। बता दे कि महिला एवं बाल विकास विभाग ने सुरक्षित मातृत्व एवं सार्वजनिक स्थल पर महिलाओं को अपने बच्चों को स्तनपान कराने के लिए जिला मुख्यालय के कलेक्ट्रेट, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, वन स्टाप सेंटर सहित मुलताई के बस स्टैंड पर आंचल कक्ष बनवाए थे।

अब हर दिन स्कूलों में ली जाएगी स्वच्छता की शपथ

19 हफ्तों की प्रभात फेरी के बाद अब स्वच्छता बनेगी बच्चों की आदत

बैतूल। स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024-25 के अंतर्गत जिले में चल रही 'स्वच्छता की पाठशाला अब नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर हो गई है। अब तक इस अभियान के अंतर्गत जिले के हजारों बच्चों की सहभागिता से 19 सप्ताह तक लगातार प्रभात फेरियां आयोजित की गई, जिसमें बच्चों ने पूरे शहर को स्वच्छता का संदेश दिया। अब इस मुहिम को और प्रभावी बनाते हुए लाडो फाउंडेशन द्वारा एक नई पहल स्वच्छता की शपथ की शुरुआत की गई है।

विगत 30 सितंबर 2024 को आयोजित स्वच्छता की पाठशाला कार्यक्रम के तहत लाडो फाउंडेशन के संस्थापक अनिल यादव ने जिला कलेक्टर, जिला शिक्षा अधिकारी और मुख्य नगर पालिका अधिकारी बैतूल को पत्र लिखकर अनुरोध किया कि जिले के सभी शासकीय एवं निजी विद्यालयों में प्रतिदिन प्रार्थना सभा के दौरान स्वच्छता की शपथ अनिवार्य रूप से दिलाई जाए।

इस पहल की शुरुआत सर्वोदय स्कूल चंद्रशेखर वार्ड, नवीन विद्या मंदिर पटेल वार्ड, द्रोणा पब्लिक स्कूल पटेल वार्ड, संकल्प विद्या मंदिर लोहिया वार्ड गंज और वीणावादिनी पब्लिक स्कूल पाढर से की गई। इन सभी स्कूलों में विद्यार्थियों ने बड़े उत्साह और संकल्प के साथ स्वच्छता की शपथ ली। स्कूल संचालकों एवं प्राचार्यों ने भी इस पहल को स्वीकारा और लाडो फाउंडेशन के प्रयासों की सराहना की।

जीवन शैली का हिस्सा बनेगी स्वच्छता– संस्था के संस्थापक अनिल यादव ने बताया कि अब तक प्रभात फेरियों के माध्यम से बच्चों और नागरिकों को जागरूक किया गया, लेकिन अब समय आ गया है कि इसे जीवन शैली का हिस्सा बनाया जाए। जब बच्चे हर दिन स्वच्छता का संकल्प खुद की जुबान से दोहराएंगे, तो स्वच्छता उनके व्यवहार और संस्कारों में रच-बस जाएगी और समाज स्वतः ही स्वच्छ बनेगा। प्राचार्यों ने इस कदम को सोच से संस्कार तक की यात्रा का नाम दिया और इसे बच्चों के व्यक्तित्व निर्माण का अहम हिस्सा बताया। लाडो फाउंडेशन की मंशा है कि आने वाले समय में जिले के प्रत्येक स्कूल में यह कार्यक्रम नियमित रूप से हो और इसके लिए जिला प्रशासन एवं शिक्षा विभाग से सतत संवाद किया जा रहा है।

नशे से दूरी है जरूरी, जनजागरूकता अभियान का शुभारंभ

बैतूल पुलिस ने पत्रकारों को दिलाई नशा मुक्ति की शपथ

बैतूल। नशे से दूरी, है जरूरी... जनजागरूकता अभियान का शुभारंभ पुलिस कंट्रोल रूम बैतूल में किया गया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक निश्चल एन. झारिया एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती कमला जोशी, कोतवाली थाना प्रभारी श्री डेहरिया, एफएसएल के आबिद अंसारी आदि की उपस्थिति में जिले के समस्त प्रमुख मीडिया प्रतिनिधियों, जिनमें पत्रकार कल्याण परिषद जिला इकाई बैतूल के वरिष्ठ पत्रकार संभागीय प्रभारी राधेश्याम सिन्हा, महासचिव हरिभूमि के ब्यूरो प्रमुख संजय द्विवेदी, पीपुल्स

समाचार के ब्यूरो प्रमुख देवेश दुबे, अंशुल शुक्ला आदि पत्रकारों के साथ एक संवाद एवं शपथ कार्यक्रम आयोजित किया गया। दरअसल पुलिस महानिदेशक मप्र. कैलाश मकवाना के निर्देशन में मध्यप्रदेश पुलिस द्वारा समस्त जिलों में 15 जुलाई से 30 जुलाई 2025 तक चलाए जा रहे राज्यव्यापी नशे से दूरी है जरूरी जनजागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक ने अभियान के उद्देश्यों एवं समाज में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति के दुष्परिणामों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि नशीले पदार्थों का सेवन न केवल युवा पीढ़ी के भविष्य को अंधकार में धकेल रहा है, बल्कि यह अपराधों की बढ़ती घटनाओं का भी प्रमुख कारण बन रहा है। समाज को जागरूक करना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है और मीडिया इस दिशा में सबसे प्रभावशाली माध्यम है। कार्यक्रम में उपस्थित पत्रकारों को नशामुक्त रहने एवं समाज को जागरूक करने की सामूहिक शपथ दिलाई गई। साथ ही अभियान के तहत आयोजित किए जाने वाले विविध कार्यक्रमों की रूपरेखा भी साझा की गई, जिनमें रैलियां, पोस्टर/बैनर प्रचार, नुक्कड़ नाटक, स्कूल/कॉलेज स्तर पर प्रतियोगिताएं, डिजिटल प्रचार, सोशल मीडिया अभियान आदि शामिल हैं। बैतूल पुलिस द्वारा अभियान की यह सशक्त शुरुआत न केवल एक प्रशासनिक पहल है, बल्कि समाज को नशे के विरुद्ध एकजुट करने की दिशा में एक प्रेरणादायक कदम भी है।

लायंस क्लब बैतूल सिटी की बागडोर अब लायन बीआर कुबड़े के हाथ में

लायंस ऑफ बैतूल के शपथग्रहण समारोह ने रचा इतिहास

बैतूल। सेवा, समर्पण और सद्भावना के प्रतीक लायंस क्लब बैतूल सिटी ने सामाजिक समर्पण की प्रेरक परंपरा को आगे बढ़ाते हुए गरिमामय संयुक्त इंस्टॉलेशन समारोह का आयोजन किया गया। लायंस ऑफ बैतूल के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में लायंस क्लब बैतूल सिटी, लायंस क्लब महक एवं लायंस क्लब बैतूल अमिगोस ने सहभागिता की। इस अवसर पर पुरानी कार्यकारिणी द्वारा किए गए कार्यों का ब्यौरा प्रस्तुत कर नई कार्यकारिणी को आगे काम करने के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई। समारोह के मुख्य अतिथि एवं इंस्टॉलेशन अधिकारी पीएमजेएफ लायन पंकज मारू (नागदा) ने अपने प्रभावशाली उद्बोधन से समारोह को वैचारिक ऊंचाईयां प्रदान की। उन्होंने अपने संबोधन में बाल मानसिक स्वास्थ्य पर चर्चा की एवं बच्चों की बौद्धिक अक्षमता के मुख्य कारणों, बचाव,सावधानियां व जन-

जागरूकता की महत्वपूर्ण बातों को साझा किया। उन्होंने बैतूल क्लब की संगठनात्मक एकता एवं उपलब्धियों की मुक्त कंठ से सराहना की। गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में पीडीजीएमजेएएफ लायन पी. एस. बग्गा, विशेष अतिथि रीजन चेयरपर्सन लायन डॉ.शिरीष अग्रवाल (हरदा) एवं जोन चेयरपर्सन लायन आशीष जैन (मुलताई) की उपस्थिति ने समारोह को गौरवशाली स्वरूप प्रदान किया। यह ऐतिहासिक अवसर तीनों क्लबों के वरिष्ठ लायन सदस्यों, नवप्रवर्तित पदाधिकारियों और शहर के सम्माननीय नागरिकों की उपस्थिति से और अधिक भव्य एवं वैभवशाली बन गया। क्लब की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी में अध्यक्ष एमजेएफ लायन बी.आर.कुबड़े, सचिव एमजेएफ लायन अक्षय अग्रवाल, कोषाध्यक्ष लायन शिशिर कुमार एवं अन्य पदाधिकारियों ने अपने दायित्व निर्वहन की शपथ ली। अध्यक्ष बीआर कुबड़े ने मंच से अपने क्लब की भावी योजनाओं और सामाजिक प्रतिबद्धताओं को साझा किया। इस समारोह ने न केवल तीनों क्लबों की एकता, संगठनात्मक समर्पण और सामाजिक दायित्व को उजागर किया, बल्कि भविष्य में सेवाकार्य की नई दिशा भी निर्धारित की। कार्यक्रम का सफल संचालन एमजेएफ लायन रविन्द्र कौर बग्गा एवं लायन हिमांशी धोटे ने किया। अंत में लायंस क्लब बैतूल सिटी से ओर से वरिष्ठ सदस्य एमजेएफ लायन रामप्रकाश गुगनानी ने सेवा का संकल्प दोहराते हुए आभार व्यक्त किया। शपथ ग्रहण कार्यक्रम में नगर के गणमान्य नागरिक, पत्रकार एवं बड़ी संख्या में लायंस क्लब के सदस्य बैतूल, मुलताई, हरदा, भोपाल, उज्जैन के सदस्य मौजूद थे।

26वें वर्ष में पाकिस्तान बार्डर पहुंचेगा राष्ट्र रक्षा मिशन

ऑपरेशन सिंदूर के बाद सैनिकों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधने उत्साहित है बैतूल की बेटियां

बैतूल। कारगिल विजय के बाद बैतूल की धरा से शुरु हुई सैनिकों की हौसला अफजाई की परम्परा अनवरत जारी है। चाहे भूकंप आए हो या भूस्खलन हुआ हो, चाहे आंदोलन की वजह से कर्फ्यू लगा हो या फिर ट्रेन ही रद्द क्यों न हुई हो, लेकिन बैतूल की बेटियों ने कभी भी अपने कदम पीछे नहीं लिए। हर वर्ष बैतूल सांस्कृतिक सेवा समिति का राष्ट रक्षा मिशन रक्षाबंधन का पर्व देश की फ्रंट लाईन पर खड़े योद्धाओं के साथ मनाता रहा है। रजत जयंती वर्ष में समिति ने बैतूल से बस से भारत पाक सीमा बाड़मेर पहुंचकर इतिहास रचा था। दो महीने पहले ही पूरे देश ने ऑपरेशन सिंदूर में देश की तीनों सेनाओं का शौर्य और पराक्रम देखा इसी से उत्साहित बैतूल की बेटियां पाकिस्तान बार्डर पर तैनात जवानों के साथ रक्षा बंधन का पर्व मनाएंगी। समिति का 30 सदस्यीय दल इस वर्ष भारत पाक सीमा पर पहुंचकर सीमा सुरक्षा बल के सैकड़ों जवानों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर उनके प्रति कृतज्ञता भी व्यक्त करेगा। बैतूल सांस्कृतिक सेवा समिति की संस्थापक गौरी बालापुरे पदम ने बताया कि पिछले ढाई दशक में बैतूल की राखियां लेकर यहां की बेटियां देश की चातुर्दिक सीमाओं पर पहुंची है। 25 वर्षों की लम्बी यात्रा में बैतूल के जनप्रतिनधियों, सामाजिक संगठनों, समाजसेवियों एवं अन्य लोगों ने सहयोग एवं प्रोत्साहन दिया है। इस वर्ष 9 एवं 10 अगस्त को रक्षा बंधन का पर्व भारत पाक सीमा पर मनाने को लेकर तैयारियां शुरु हो गई है। श्रीमती पदम ने बताया कि जिन सरहदों पर संस्था का दल पूर्व में रक्षाबंधन मना चुका है वहां राखियां पोस्ट के माध्यम से पहुंचेगी।

जनसुनवाई में प्राप्त शिकायतों के निराकरण में कोताही न बरतें अधिकारी: सीईओ

जनसुनवाई में सुनीं नागरिकों की समस्याएं

बैतूल। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अक्षत जैन ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में प्रातः 11 बजे से आयोजित जनसुनवाई में नागरिकों की समस्याएं सुनीं। इस दौरान उन्होंने अनेक समस्याओं का निराकरण मौके पर ही किया। जनसुनवाई में सभी विभागीय अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित थे। जनसुनवाई में कुल 137 आवेदन प्राप्त हुए। सीईओ श्री जैन ने जनसुनवाई में प्राप्त आवेदनों का निराकरण गंभीरता पूर्वक किए जाने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि प्राप्त शिकायतों के निराकरण में कोताही न बरती जाए। इस अवसर पर अपर कलेक्टर राजीव नंदन श्रीवास्तव, डिप्टी डायरेक्टर श्रीमती तृप्ति पटेरिया ने भी नागरिकों की समस्याएं सुनीं। जनसुनवाई में आवेदन के माध्यम से भीमपुर तहसील के ग्राम मक्का निवासी सीलकराम ने अनावेदकों द्वारा पटवारी और आरआई से सांठगांठ कर भूमि का नक्शा काटे जाने की शिकायत की। प्राप्त आवेदन पर सीईओ श्री जैन ने भैंसदेही एसडीएम को प्रकरण के निराकरण के निर्देश दिए। बैतूल निवासी दयाल सिंह ने राजस्व फाइल उपलब्ध कराए जाने के लिए आवेदन दिया। प्राप्त आवेदन पर सीईओ श्री जैन ने मुलताई एसडीएम को प्रकरण के निराकरण के निर्देश दिए।

सडक़ और नाली निर्माण किए जाने की मांग– बैतूल की ग्राम पंचायत दनोरा निवासी तुलाराम हरफोड़े ने दनोरा-टेमनी रिहायशी इलाके में सडक़ और नाली निर्माण किए जाने के लिए आवेदन दिया। प्राप्त आवेदन पर जिला पंचायत सीईओ श्री जैन ने बैतूल एसडीएम को प्रकरण की जांच कर निराकरण के निर्देश दिए। जनसुनवाई में अंबेडकर वार्ड निवास अमित राठौर ने आवेदन के माध्यम से शासकीय भूमि पर हुए अवैध अतिक्रमण को हटाए जाने की मांग की। प्राप्त आवेदन पर सीईओ श्री जैन ने नगर पालिका बैतूल सीएमओ और तहसीलदार को प्रकरण के निराकरण के निर्देश दिए। बैतूल निवासी प्रहलाद मतलाने ने मुलताई स्थित भूमि की जांच किए जाने के लिए आवेदन दिया। जिस पर सीईओ श्री जैन ने मुलताई तहसीलदार को प्रकरण की जांच के निर्देश दिए।

सोयाबीन फसलों में सफेद लट का प्रकोप

बैतूल। कृषि विज्ञान केन्द्र बैतूल के पौध संरक्षण वैज्ञानिक आरडी बारपेटे एवं अनुविभागीय कृषि अधिकारी श्री दीपक सरियाम ने मंगलवार को बैतूल विकासखंड के विभिन्न गांवों के खेतों का भ्रमण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने सोयाबीन की फसलों में भूमि जनित कीट सफेद लट व्हाइट गृब के प्रकोप की पुष्टि की। यह कीट क्षेत्रीय किसानों के बीच साबरदेही, खोदा या उडंन के नाम से भी जाना जाता है। पहले यह कीट मुख्यतः सब्जी एवं कंद फसलों को प्रभावित करता था, परंतु अब यह सोयाबीन एवं मक्का जैसी मुख्य फसलों में भी गंभीर नुकसान पहुंचा रहा है। प्रकोप के लक्षणों के बारे में जानकारी देते हुए वैज्ञानिकों ने बताया कि सफेद लट पौधों की जड़ों को खाकर उन्हें

कमजोर कर देती है, जिससे पौधे बिना किसी बाहरी लक्षण के अचानक सूखने लगते हैं। प्रकोपित पौधे आसानी से उखड़ जाते हैं। कीट की इल्ली सफेद और मोटी होती है तथा अंग्रेजी के 'सी' आकार में मुड़ी रहती है, जिसका सिर गहरे भूरे रंग का होता है। विशेषज्ञों ने बताया कि खेतों में कच्चे गोबर की खाद एवं पूर्व फसल के अवशेष इस कीट की संख्या को बढ़ाने में सहायक होते हैं। इसके वयस्क कीट तांबई रंग के होते हैं जो रात्रि के समय सक्रिय रहते हैं और पौधों की पत्तियां खाकर उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं।

कीट नियंत्रण एवं प्रबंधन के उपाय– मूंगफली एवं अन्य ग्रसित फसलों के बीजों को क्लोरपायरीफास 20 ई.सी. कीटनाशक से 25 मिली/किग्रा की दर से उपचारित करें। खेत की मेंड़ और आसपास की झाडिय़ों पर क्लोरपायरीफास 2.5 मिली, लीटर पानी का छिडक़ाव करें। क्लोरपायरीफास दानेदार (20 किग्रा/हेक्टेयर) या फिप्रोनिल दानेदार (10 किग्रा/हेक्टेयर) को भूमि में मिलाएं। मेटाराइजियम एनीसोप्ली जैव कीटनाशी को 1200 मि.ली./हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। इसके अलावा क्लोरपायरीफास 20 ई.सी. (5 लीटर/हेक्टेयर) को 50-100 किग्रा गोबर या केंचुआ खाद में मिलाकर पर्याप्त नमी वाली भूमि में भुरकाव करें। वैज्ञानिकों ने किसानों से अपील की है कि वे नियमित रूप से फसलों की निगरानी करें और समय रहते कीट नियंत्रण उपाय अपनाकर अपनी फसल को नुकसान से बचाएं।

कार्यालय नगरपालिका परिषद बैतूल (म.प्र.)

क्रमांक/लो.नि.शा./ई./5092 से 5094 बैतूल दिनांक 08/07/2025

// ई-टेन्डर आमंत्रण सूचना //
(प्रथम निविदा आमंत्रण सूचना)

निम्नलिखित कार्य हेतु केन्द्रीकृत प्रणाली में पंजीकृत ठेकेदारों से ऑनलाईन निविदायें आमंत्रित की जाती है। निविदा का विस्तृत विवरण वेबसाइट https://mptenders.gov.in/nicgep/app पर देखा जा सकता है।

क्र.	ऑनलाईन निविदा क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की समयावधि एवं लागत	निविदा प्रपत्र का मूल्य एवं EMD	निविदा की अंतिम तिथि
1	2025_UAD_435636_1 1st call	CONSTRUCTION OF CC ROAD WEARING COAT FROM MUNNA PRADHAN GALI AND HANUMAN MANDIR GALI IN GANESH WARD BETUL	1- 50 Days 2- 1143712/-	1- 2000/- 2-8600/-	08/08/2025
2	2025_UAD_435637_1 1st call	CONSTRUCTION OF CC ROAD WEARING COAT FROM RAJU MAHARAJ GALI AND VINOD BUNDELA GALI IN GANESH WARD BETUL	1- 50 Days 2- 1159336/-	1- 2000/- 2-8700/-	08/08/2025
3	2025_UAD_435895_1 1st call	CONSTRUCTION OF CC ROAD AND HP CULVERT IN FRONT OF HMT FACTORY TIKARI JOD MARG IN AMBEDKAR WARD BETUL	1- 65 Days 2- 8694408/-	1- 10000/- 2- 65200/-	08/08/2025

नोट :- निविदा से संबंधित किसी भी प्रकार के संशोधन का प्रकाशन ऑनलाईन https://mptenders.gov.in/nicgep/app की वेबसाईड पर ही किया जावेगा, पृथक से समाचार पत्र में प्रकाशन नही किया जावेगा।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद बैतूल

शासन की योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन कर हितग्राहियों तक सुगमता से पहुचाएं लाभ- कलेक्टर श्री विश्वकर्मा

● टीएल बैठक में कलेक्टर श्री विश्वकर्मा ने की सीएम हेल्पलाईन और विभागीय गतिविधियों की समीक्षा

रायसेन (निप्र)। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित टीएल बैठक में कलेक्टर श्री अरूण कुमार विश्वकर्मा द्वारा सीएम हेल्पलाईन, विभागीय गतिविधियों और योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। कलेक्टर श्री विश्वकर्मा ने जिला अधिकारियों को निर्देश दिए कि शासन की जनकल्याणकारी और हितग्राहीमूलक योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन किया जाए तथा प्रत्येक पात्र हितग्राही तक इन योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाए। उन्होंने सीएम हेल्पलाईन शिकायतों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिकायतों का समयावधि में संतुष्टिपूर्ण निराकरण सुनिश्चित कराएं।

कलेक्टर श्री विश्वकर्मा ने विभागवार सीएम हेल्पलाईन शिकायतों के निराकरण तथा प्रदेश स्तर पर ग्रेडिंग की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि शिकायतों के प्राप्त होते ही निराकरण की कार्यवाही की जाए। उन्होंने महिला बाल विकास विभाग, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, ऊर्जा विभाग सहित अन्य विभागों में शिकायतों के निराकरण में बेहतर काम होने पर अधिकारियों की सराहना की। इसी प्रकार शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, वन विभाग, लोक निर्माण विभाग, उच्च शिक्षा विभाग की सीएम हेल्पलाईन शिकायतों की संख्या अधिक होने तथा निराकरण नहीं होने पर संबंधित जिला अधिकारियों को गंभीरतापूर्वक शिकायतों का

निराकरण कराने के निर्देश दिए। कलेक्टर श्री विश्वकर्मा ने निर्देश दिए कि शिकायर्ता से भी संवाद कर निराकरण की कार्यवाही से अवगत कराया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि कोई भी शिकायत नॉन अटेन्डेन्ट ना रहे।

बैठक में कलेक्टर श्री विश्वकर्मा ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की समीक्षा करते हुए स्वीकृत आवास, हितग्राहियों को किश्त वितरण और आवासों की निर्माण की स्थिति की समीक्षा करते हुए कहा कि आवासों का कार्य शीघ्र पूर्ण कराएं। इसी प्रकार पीएम आवास योजना शहरी 2.0 के तहत प्राप्त आवेदनों को स्वीकृत करने और जियो टैगिंग कार्य की भी जानकारी लेते हुए कार्य शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए। कृषि विभाग की समीक्षा के दौरान कलेक्टर श्री विश्वकर्मा ने जिले में बोवनी की स्थिति की जानकारी लेते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी सोसायटी में पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध रहे। साथ ही निजी खाद विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों का निरीक्षण करने और खाद के सैम्पल लेकर जांच कराने के निर्देश अधिकारियों को दिए।

महिला बाल विकास विभाग की समीक्षा करते हुए कलेक्टर श्री विश्वकर्मा ने निर्माणाधीन आंगनवाड़ी भवनों की जानकारी लेते हुए निर्माण कार्य गुणवत्ता के साथ शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिए। जनपद पंचायत सीईओ को भी निर्माणाधीन आंगनवाड़ी भवनों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने लाड़ली बहना योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, मुख्यमंत्री बाल आरोग्य संवर्धन योजना की समीक्षा कर दिशा-निर्देश दिए। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान कलेक्टर श्री विश्वकर्मा ने सीएमएचओ को निर्देश दिए कि सभी स्वास्थ्य केन्द्रों में पर्याप्त मात्रा में आवश्यक दवाईयां उपलब्ध रहें। उन्होंने सभी हितग्राहियों के शीघ्र आयुष्मान कार्ड बनाए जाने के संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए। लोक निर्माण विभाग की समीक्षा के दौरान कार्यपालन यंत्री को मरम्मत के कार्यो पर विशेष ध्यान देने के निर्देश देते हुए कहा कि आवश्यकतानुसार सड़कों, पुल-पुलियों की मरम्मत कार्य किया जाए।

कलेक्टर श्री विश्वकर्मा ने पशुपालन एवं डेयरी विकास विभाग की समीक्षा करते हुए जिले में गौशालाओं के संचालन की जानकारी लेते हुए गौशालाओं का निरीक्षण कर व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। साथ ही सड़कों पर गौवंश ना रहे इसके लिए भी अधिकारियों को निर्देशित किया। बैठक में शिक्षा विभाग, आदिम जाति कल्याण विभाग, सामाजिक न्याय विभाग, वन विभाग, खनिज विभाग, परिवहन विभाग सहित विभिन्न विभागों के कार्यो और योजनाओं की समीक्षा की गई।

कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिला पंचायत सीईओ श्रीमती अंजू पवन भदौरिया, अपर कलेक्टर श्रीमती श्वेता पवार सहित विभिन्न विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित रहे। अनुभागों से एसडीएम, जनपद सीईओ, सीएमओ सहित विकासखण्ड स्तरीय अधिकारी वीडियो कॉफ्रेंस के माध्यम से बैठक में उपस्थित रहे।

पीएम आवास योजना की मदद से भगवत सिंह और उनके परिवार का पक्के मकान का सपना हुआ पूरा

रायसेन (निप्र)। प्रधानमंत्री जनमन योजना विशेष पिछड़ी जनजाति वर्ग के लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है। इसके तहत शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का सीधा-सीधा लाभ इन समुदाय के लोगों को मिल रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार और प्रदेश के मुखिया डॉ मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश सरकार आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की स्वयं के पक्के मकान के सपने को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर कार्य कर रही है। रायसेन जिले के सांची जनपद के ग्राम मुक्तापुर में हितग्राही श्री भगवत सिंह और उनका परिवार प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत पक्का मकान बन जाने से बेहद खुश हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी तथा मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव को धन्यवाद देते हुए हितग्राही श्री भगवत सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ने उनके वर्षो पुराने सपने को साकार किया है। योजना के तहत आवास की स्वीकृति मिलते ही पंचायत स्तर पर दस्तावेजों की पूर्ति होने के साथ ही आवास निर्माण प्रारंभ किया गया। जिसमें पहली किश्त की राशि मिलते ही उनकी मकान निर्माण की उम्मीद पक्की होने लगी। मकान निर्माण आगे बढ़ने के साथ ही प्रगति के आधार पर किश्त की राशि

मिलती गई और देखते ही देखते उनके सपनों का आशियाना पूरा होकर तैयार हो गया। हितग्राही ने बताया कि आवास निर्माण में कार्य करने पर मनरेगा के तहत उन्हें मजदूरी का भुगतान भी किया गया। हितग्राही श्री भगवत सिंह अपने पुराने दिनों की कठिनाई याद करते हुए बताते हैं कि आवास निर्माण से पहले उनका परिवार कच्ची झोपड़ीनुमा घर में निवास करता था। जहां जीवन व्यतीत करना बहुत कठिन था। अब पक्का मकान मिलने से उनकी समस्याएं दूर हो गई हैं। पक्की छत वाली घर होने से उनकी समाज में प्रतिष्ठा बढ़ी है। नए आवास में परिवार के साथ हंसी-खुशी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड, संबल कार्ड सहित शासन की विभिन्न महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ उनके परिवार को मिल रहा है।

संक्षिप्त समाचार

एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत किया गया पौधारोपण

सीहोर (निप्र)। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से जन अभियान परिषद के सदस्यों द्वारा ग्राम करंजखेड़ा में पौधरोपण किया। इस अवसर पर ने पर्यावरण और रोपित किए गए पौधों के संरक्षण का संकल्प भी लिया। इसके साथ ही सभी ग्रामवासियों को अधिक से अधिक पौधरोपण के लिए प्रेरित किया गया। इस अवसर पर सीहोर विकासखंड समन्वयक श्री प्रदीप सिंह सेंगर सहित अन्य सदस्य उपस्थित थे।

रोजगार मेले में 68 अभ्यर्थियों का चयन

बैतूल (निप्र)। जिला रोजगार कार्यालय, आईटीआई, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के संयुक्त तत्वाधान में युवा संगम के तहत शुक्रवार को जिला स्तरीय रोजगार, स्वरोजगार एवं अप्रेन्टिसशिप मेले का आयोजन शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था बैतूल में किया गया। जिला रोजगार अधिकारी ने बताया कि रोजगार मेले में कुल 158 आवेदकों ने पंजीयन कराया था। जिसमें 07 कम्पनियों के द्वारा 68 आवेदकों का प्राथमिक रूप से चयन कर 04 को लेटर ऑफ इंटेन्ट प्रदान किए गए। रोजगार मेले के साथ ही आईटीआई में स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्वास्थ परिक्षण शिविर भी आयोजित किया गया। स्वास्थ्य शिविर में 92 मरीजों की स्वास्थ्य जांच की गई, जिसमें 36 जांच सिकलसेल की गई।

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत ग्राम साल्याखेड़ी में जागरूकता शिविर सम्पन्न

हरदा (निप्र)। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत शुक्रवार को जिले के ग्राम साल्याखेड़ी के आंगनवाड़ी केन्द्र में जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। शिविर में परियोजना अधिकारी श्रीमती सीमा जैन ने उपस्थित प्रतिभागियों को विभागीय योजनाओं की जानकारी दी गई। शिविर में बाल विवाह रोकथाम संबंधी नियमों व कानूनों तथा पाक्सों एक्ट के बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं को वन स्टॉप सेंटर में दी जाने वाली निःशुल्क सेवाओं, महिला हेल्पलाइन नम्बर 1090, चाईल्ड हेल्पलाइन नम्बर 1098, साइबर हेल्पलाइन नम्बर व सीएम हेल्पलाइन 181 के बारे में जानकारी दी गई। शिविर में उपस्थित महिलाओं को एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत पौधरोपण करने के लिये प्रेरित भी किया गया। शिविर में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व महिलाएं उपस्थित थी।

मजदूरो के बच्चों का स्वास्थ्य पर नजर रखें

विदिशा (निप्र)। कलेक्टर श्री अंशुल गुप्ता ने सोमवार को लंबित आवेदनो की समीक्षा के दौरान निर्माण कार्यो को संपादित कराने वाले समस्त विभागो के जिलाधिकारियों को निर्देशित किया है कि जो मजदूर कार्य कर रहे है और उनके बच्चे साथ में रहते है तो बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण पर भी विशेष ध्यान रखा जाए।

कलेक्टर श्री गुप्ता ने कहा कि ऐसे मजदूरो के बच्चों का नजदीक की आंगनबाडी केन्द्र में पहुंचाने के प्रबंध सुनिश्चित किए जाए। उन्होंने महिला एवं बाल विकास विभाग के जिलाधिकारी को निर्देशित किया है कि जिन निर्माण कार्यो में मजदूरी की संख्या अधिक है उन क्षेत्रो में स्वंय भ्रमण कर मजदूरो के बच्चो को सुविधाएं मुहैया हो रही है कि नहीं का औचक निरीक्षण करें।

मुआवजा वितरण में विलंब होने पर कलेक्टर ने व्यक्त की घोर नाराजगी

● गौशालाओं के लिए जल्द करें भूमि का चिन्हांकन - कलेक्टर

सीहोर (निप्र)। कलेक्टर श्री बालागुरू के. की अध्यक्षता में जिला पंचायत सभाकक्ष में टीएल बैठक आयोजित की गई। बैठक में उन्होंने विभिन्न विभागों के समय-सीमा प्रकरणों और सीएम हेल्पलाइन में लंबित प्रकरणों की समीक्षा की। बैठक में कलेक्टर श्री बालागुरू के. ने सीएम हेल्पलाइन के लंबित प्रकरणों की वस्तुस्थिति की जानकारी लेते हुए समय सीमा के भीतर सभी प्रकरणों का संतुष्टिपूर्ण निराकरण करने के निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर श्री बालागुरू के. ने निर्देश दिए कि नेशनल हाईवे, रेल परियोजनाओं, सिंचाई सहित विभिन्न परियोजनाओं के लिए भू अर्जन, मुआवजा वितरण, अर्जित भूमि का नामांतरण एवं कब्जा दिलाने के कार्य में प्रगति लाई जाए।

इस दौरान उन्होंने भूअर्जन के पश्चात होने वाले मुआवजा वितरण की कार्यवाही में हो रही देरी पर घोर नाराजगी व्यक्त की और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि मुआवजा वितरण की कार्यवाही जल्द से जल्द की जाए।

बैठक में कलेक्टर श्री बालगुरू के. ने कहा कि जाति प्रमाण के अभाव में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के मामलों

में कार्यवाही में विलंब होता है। उन्होंने सभी एसडीएम को निर्देश दिए कि ऐसे मामलों में पीड़ित व्यक्तियों के जाति प्रमाण पत्र जल्द बनाए जाएं। ताकि पीड़ितों को जल्द न्याय मिल सके।

बैठक में उन्होंने निर्देश दिए कि नगरीय क्षेत्रों में समग्र ईकेवाईसी का कार्य तेजी से किया जाए। इसके साथ ही जिले में बड़ी गौशालाओं के लिए भूमि चिन्हित की जाए। बैठक में कलेक्टर श्री बालागुरू के. ने निर्देश दिए कि जिले में पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए तथा किसानों को समय पर आवश्यक मात्रा में उर्वरक उपलब्ध कराया जाए। इसके लिए उर्वरकों का जिले से बाहर अनियमित रूप से स्थानांतरण एवं निर्यात प्रतिबंधित किया गया है, इसका कढ़ाई से पालन किया जाए, ताकि जिले में उर्वरकों की कमी न हो। इसके साथ ही जिले में उर्वरकों की उपलब्धता के संबंध में किसानों जानकारी भी दी जाए। बैठक में कलेक्टर श्री बालागुरू के. ने जिले में गत दिवस हुई दुर्घटनाओं को दृष्टिगत रखते हुए निर्देश दिए कि जिले के सभी बांधों, झरनों, जोखिमपूर्ण पर्यटन स्थलों, पुल-पुलियों पर वर्षा के दौरान पर्यटकों एवं नागरिकों को जाने से रोका जाए तथा निगरानी रखी जाए। जलभराव या बाढ़ की स्थिती में आवागमन को रोकने के लिए जिन कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है, उनकी उपस्थिती सुनिश्चित की जाए। उन्होंने सभी एसडीएम एवं संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिले के वॉटरफॉल एवं अन्य जोखिमपूर्ण स्थानों पर संभावित दुर्घटनाओं को रोकने के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है, उस आदेश का कढ़ाई से पालन सुनिश्चित कराया जाए। उन्होंने कहा कि रेस्क्यू टीम को अलर्ट मोड पर रखा जाए तथा सूचना मिलते ही त्वरित राहत एवं बचाव की कार्रवाई की जाए।

कलेक्टर श्री बालागुरू के. ने जिले के आईटीआई, पॉलिटेक्निक कॉलेज तथा डिग्री कालेजों में क्षमतानुसार शत प्रतिशत सीटों पर प्रवेश कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्कूलों से 10वी एवं 12वीं उत्तीर्ण विद्यार्थियों की सूची प्राप्त कर यह सुनिश्चित करें सभी बच्चे अगली कक्षा में प्रवेश लें तथा कोई भी बच्चा ड्राप आउट न करें। उन्होंने कहा कि यदि कोई विद्यार्थी ड्रॉपआउट कर रहा है तो इसका कारण पता करें और उसे कॉलेज में एडमिशन के लिए प्रोत्साहित करें। बैठक में जिला पंचायत सीईओ डॉ नेहा जैन, अपर कलेक्टर श्री वृंदावन सिंह, संयुक्त कलेक्टर सुश्री वंदना राजपूत, श्री आनंद सिंह राजावत, एसडीएम श्री नितिन टाले, श्री जमील खान, श्री तन्मय वर्मा, डिप्टी कलेक्टर श्रीमती स्वाती मिश्रा, श्री सुधीर कुशवाह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

विधायक ने मूंग उपार्जन केन्द्र का शुभांरभ किया

विदिशा (निप्र)। समर्थन मूल्य पर मूंग उपार्जन कार्य जिले में नौ केन्द्रो पर क्रियान्वित किया जा रहा है। विदिशा विधायक श्री मुकेश टण्डन ने विदिशा विकासखण्ड के ग्राम पठारी हवेली के उपार्जन केन्द्र का शुभांरभ किया। उपार्जन केन्द्र पर सबसे पहले श्री खूबसिंह दांगी ने 13 क्विंटल 50 किलो और हल्की बाई ने 22 क्विंटल 50 किलो मूंग समर्थन मूल्य पर विक्रय हेतु तुलवाई की गई है।

विधायक श्री मुकेश टण्डन ने मध्यप्रदेश वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन की पठारी हवेली गोदाम में पहुंचकर समर्थन मूल्य पर मूंग उपार्जन कार्य का विधिवत शुभांरभ करते हुए अपने समक्ष कृषक की मूंग को तुलवाया है। इससे पहले उन्होंने कृषक का फूल माला पहनाकर स्वागत किया।

गौरतलब हो कि समर्थन मूल्य 8682 रूपए प्रति क्विंटल की दर पर किसानो से क्रय की जा रही है। उपार्जन केन्द्र पर किसानो को मूंग फसल विक्रय में दिक्कत ना हो इसके लिए स्लाट बुकिंग के आधार पर उन्हें सूचनाएं सम्प्रेषित की जा रही है। उपार्जन केन्द्र पर बारिश के दौरान तुलाई व भण्डारण में कहीं कोई दिक्कत ना हो के प्रबंध सुनिश्चित किए गए है।

कलेक्टर ने प्रतिबंधात्मक आदेश निरस्त किया

हरदा (निप्र)। हरदा 14 जुलाई 2025/ कलेक्टर श्री सिद्धार्थ जैन ने बताया कि जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति नियंत्रण में है। इसके फलस्वरूप, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 अर्थात पूर्व सीआरपीसी की धारा 144 के तहत एक जगह पर व्यक्तियों के एकत्रित होने पर लगाया गया प्रतिबंधात्मक आदेश निरस्त कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, कानून व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखने के उद्देश्य से, 13 जुलाई, 2025 को सड़क मार्ग अवरुद्ध करने वाले व्यक्ति, जिन्हें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 170 के तहत गिरफ्तार किया गया था, अब रिहा किए जा रहे हैं।

मार्ग अवरुद्ध करने वाले रिहा हुए

कलेक्टर श्री विश्वकर्मा की अध्यक्षता में जिला बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति की बैठक सम्पन्न

रायसेन (निप्र)। जिला बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति की बैठक कलेक्टर श्री अरूण कुमार विश्वकर्मा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में सम्पन्न हुई।

बैठक में कलेक्टर श्री विश्वकर्मा ने स्पॉन्सरशिप योजना, समेकित बाल संरक्षण योजना, पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन योजना, मुख्यमंत्री कोविड 19 बाल सेवा योजना सहित विभाग की अन्य योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि विभिन्न बाल संरक्षण योजनाओं के तहत बालकों का संरक्षण पूरी संवेदनशीलता के साथ किया जाए।

बैठक में समिति के सदस्यों द्वारा बाल श्रमिकों की ओर ध्यान आकृष्ट कराने पर कलेक्टर श्री विश्वकर्मा ने अधिकारियों को बाल श्रम और भिक्षावृत्ति पर रोक लगाने हेतु अधिकारियों को निर्देश दिए।

बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्रीमती अंजू पवन भदौरिया, अपर कलेक्टर श्रीमती श्वेता पवार, समिति के सदस्य और अधिकारी उपस्थित रहे। महिला बाल विकास विभाग के जिला अधिकारी श्री बृजेश कुमार जैन द्वारा बताया गया कि मुख्यमंत्री कोविड 19 बाल सेवा योजना के तहत कोविड-19 महामारी के दौरान 01 मार्च 2021 से 31 जून 2021 की अवधि में जिन बच्चों के माता-पिता की मृत्यु हुई, उन बच्चों को पांच हजार रू प्रतिमाह तथा निःशुल्क खाद्यान्न एवं शिक्षा दिए जाने का प्रावधान है।

जिले में मुख्यमंत्री कोविड 19 बाल सेवा योजना के तहत 28 बच्चों को चिन्हांकित कर योजना का लाभ दिया गया है।स्पांसरशिप योजना के तहत निराश्रित, अनाथ, बेसहारा बालकों को योजना के तहत प्रतिमाह प्रति बालक चार हजार रू के मान से राशि दिए जाने का प्रावधान है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 262 बालकों को योजना से लाभान्वित किया गया है।

शिकायती समितियों को उपार्जन कार्यो से संलग्न नहीं करने के निर्देश

विदिशा (निप्र)। कलेक्टर श्री अंशुल गुप्ता ने जिले में पिछले पांच वर्षो के दरम्यिान जिन-जिन सहकारी समितियों की शिकायते दर्ज की गई है कि सूची उपलब्ध कराने के निर्देश कॉ-आपरेटिव बैंक के सीईओ श्री विनय प्रकाश सिंह को दिए है।

सोमवार को लंबित आवेदनो की समीक्षा बैठक के दौरान कलेक्टर श्री गुप्ता ने कहा कि जिन समितियों की शिकायते दर्ज हुई है उन्हें उपार्जन कार्यो से पृथक रखा जाए। कलेक्टर श्री गुप्ता ने सभी एसडीएमो को निर्देशित किया है कि प्रत्येक सहकारी समितियों के लिए एक-एक नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए है उनके द्वारा संपादित किए जाने वाले कार्यो की मानिटरिंग करने, समितियों में खाद, बीज की उपलब्धता की अपडेट स्थिति से अवगत रहें।

उन्होंने समितिवार पटवारियों के माध्यम से खाद विक्रय बोरियो पर मोहर लगाने की कार्यवाही का परीक्षण कराने कराने तथा किसानो के द्वारा खरीदा गया खाद के लिए उपलब्ध कराया गया आधार व मोबाइल नम्बर की क्रास मानिटरिंग क्रियान्वित कराने के निर्देश दिए है।

161 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों पर स्वास्थ्य शिविर आयोजित

नर्मदापुरम (निप्र)। नर्मदापुरम जनसमुदाय को उनके निवास के निकट स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के उदेश्य से आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (शहरी एवं ग्रामीण), एवं उपस्वास्थ्य केन्द्रों को आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के रूप में विकसित किया गया है। सीएमएचओ डॉ नरसिंह गेहलोत ने बताया कि जिनके माध्यम से हितग्राहियों को समग्र प्राथमिक स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध कराई जा रही है।

14 जुलाई सोमवार को जिले के इन आयुष्मान अरोग्य मंदिरों पर आयुष्मान आरोग्य शिविरो का आयोजन हुआ है। इन शिविरो के माध्यम से समुदाय के अंतिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। इन शिविरो में विभिन्न

रोगो की जांच, उपचार एवं आश्यकता पड़ने पर अन्य संस्थाओ में रेफरल की सुविधाएं उपलब्ध हैं। इनमें ब्लड प्रेशर की जांच, ब्लड शुगर की जांच, गर्भवती महिलाओ की जांच, शिशुओं, किशोरियों, वृद्धजनों की जांच, जिनमें दस्त रोग, निमोनिया, नेत्र विकार, मुख/दंत विकारो की जांच, मानसिक स्वास्थ्य, नाक कान गले के विकारो की जांच, क्षय रोग की जांच तथा अन्य पैथोलॉजिकल जांचे, उपचार तथा आवश्यकतानुसार रेफरल की सुविधाएं उपलब्ध होगी।

इसके साथ ही इन शिविरों में परिवार कल्याण, से संबंधित सुविधाएं भी उपलब्ध होगी।

उल्लेखनीय है कि नर्मदापुरम जिले में अब तक लगभग 161 आयुष्मान आरोग्य मंदिर विकसित किये जा चुके है, जिनमें 143 उपस्वास्थ्य केन्द्र,14 ग्रामीण प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, तथा 4 शहरी स्वास्थ्य संस्थाये शामिल है। पूर्व में जहां नागरिकों को ब्लड प्रेशर तथा ब्लड शुगर जैसी जांचो के लिए भी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा जिला अस्पताल तक जाना पड़ता था। वही अब यह सुविधाएं नागरिको के 5 से 30 मिनट की दूरी पर उपलब्ध है।आज जिले के सभी आयुष्मान आरोग्य स्वास्थ्य शिविरों में लगभग 2900 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण हुआ।

नवोदय विद्यालय की कक्षा 6 में प्रवेश के लिये 29 जुलाई तक करें आवेदन

हरदा (निप्र)। हरदा 14 जुलाई 2025/ पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय चारूवा की कक्षा 6 वीं में प्रवेश के लिये निःशुल्क पंजीयन प्रारम्भ हो चुके है।

प्राचार्य पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय चारूवा ने बताया कि वर्ष 2026 में आयोजित होने वाली इस प्रवेश परीक्षा में शामिल होने के लिये ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि को 29 जुलाई है। उन्होने बताया कि इस परीक्षा में शामिल होने के लिये ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये गये है। आवेदक विद्यार्थी की जन्म तिथि 1 मई 2014 से 31 जुलाई 2016 के बीच होना चाहिए। आवेदन हरदा जिले का मूल निवासी होना चाहिए तथा हरदा जिले के किसी शासकीय या अर्द्धशासकीय अथवा मान्यता प्राप्त विद्यालय में सत्र 2025 में कक्षा 5 वीं में उत्तीर्ण किया जाना अनिवार्य है। उन्होने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र की सुविधा का लाभ प्राप्त करने के लिये विद्यार्थी को 3री, 4थी और 5 वीं ग्रामीण क्षेत्र में स्थित विद्यालय से उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

पचमढ़ी की 395.93 हेक्टेयर जमीन अब तक डिनोटिफाई नहीं

कैबिनेट ने दो माह पहले दी थी मंजूरी, दोबारा कैबिनेट की लेनी पड़ेगी मंजूरी

भोपाल (नप्र)। कैबिनेट के फैसले के दो माह बाद भी पचमढ़ी की 395.93 हेक्टेयर जमीन फॉरेस्ट से रेवेन्यू (नजूल) घोषित करने का आदेश जारी नहीं हो सका है। इसकी वजह डिनोटिफाई की जाने वाली जमीन के खसरा नंबर एंट्री किए जाने में हुई चूक को बताया जा रहा है। ऐसे में अब अगली कैबिनेट में एक बार फिर इस प्रस्ताव को लाए जाने की तैयारी है ताकि सही खसरे नंबर्स की एंट्री किए जाने के बाद उसे कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी जा सके।

वन विभाग के अधीन पचमढ़ी की इस भूमि को डिनोटिफाई करने के लिए मोहन यादव सरकार ने 5 मई की कैबिनेट बैठक में फैसला किया था। इसके बाद यह भी तय हुआ था कि पचमढ़ी अभयारण्य का नोटिफिकेशन फिर से होगा।

अभी अभ्यारण के कारण अनुमति नहीं दे पा रही सरकार- दरअसल, मोहन सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद यह फैसला लिया था। एमपी सरकार ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 18 (1) के अंतर्गत एक जून 1977 को पचमढ़ी अभयारण्य को अधिसूचित किया था।

इस दौरान अभयारण्य में शामिल किए गए और बाहर किए जाने वाले क्षेत्र को सीमांकित नहीं किया गया था। इसके चलते यहां कोई गतिविधि सरकार खुद भी नहीं कर पा रही है। इस मामले में सरकार के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद यहां की 395.93 हेक्टेयर जमीन को नजूल भूमि घोषित करने का फैसला किया गया।

इसके बाद यह भूमि विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण के स्वामित्व में आ जाएगी और यहां विकास कार्यों में तेजी लाने व जमीन की खरीदी-बिक्री का काम किया जा सकेगा। अभी अभयारण्य होने के कारण यहां कोई व्यवसायिक गतिविधियां चलाने की अनुमति सरकार नहीं दे पा रही है। पचमढ़ी में राजा भभूत सिंह की स्मृति एवं जनजातीय समाज के कल्याण को समर्पित कैबिनेट बैठक की गई।

फैसले के बाद यह पेंच सामने आया- बताया जाता है कि कैबिनेट बैठक के बाद वन विभाग की ओर से इसका नोटिफिकेशन जारी होना था लेकिन कैबिनेट के फैसले के बाद यह बात सामने आई कि डिनोटिफाई किए जाने वाले खसरों और रकबे के नंबर एंट्री करने में गड़बड़ हो गई है।

इसके चलते नोटिफिकेशन की कार्यवाही रोक दी गई। अब जबकि नर्मदापुरम कलेक्टर ने इसे करेक्ट करा दिया है तो कहा जा रहा है कि अब इसे फिर कैबिनेट में लाकर मंजूरी दी जाएगी। इसके बाद इसका राजपत्र में प्रकाशन होगा।

व्यापारिक साझेदारियों की दिशा में दुबई यात्रा सफल : मुख्यमंत्री

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 13 से 15 जुलाई के दौरान अपने दुबई प्रवास के दौरान विभिन्न व्यापारिक बैठकों और निवेश संवाद कार्यक्रमों में शामिल हुए। दौरे के समापन पर मुख्यमंत्री ने दुबई से एक विशेष संदेश जारी कर इस यात्रा को 'विकास यात्रा की एक मजबूत नींव' बताया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा, मेरे दुबई प्रवास के दौरान अनेक व्यापारिक बैठकों का आयोजन हुआ। मैं यहां के निवेशकों, भारतीय समुदाय के नागरिकों, सरकार के अधिकारियों और भारत के महावाणिज्य दूत का हृदय से धन्यवाद करता हूं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दुबई की सामर्थ्य को पहचाना है और 2015 से ही उन्होंने इस शहर को वैश्विक व्यापार का प्रवेश द्वार बनाने की दिशा में कार्य किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी ने दुबई के माध्यम से विश्व में व्यापार के एक नए द्वार को खोलने का कार्य किया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने आगे कहा कि मध्यप्रदेश सरकार की ओर से इस 'विकास यात्रा' को इस भावना के साथ डिज़ाइन किया गया है कि यह राज्य के आर्थिक विकास और वैश्विक साझेदारियों के लिए एक मजबूत आधार बने। मुख्यमंत्री डॉ. यादव के इस दौरे के दौरान दुबई स्थित डीपी वर्ल्ड, जाएफजा (जेबेल अली फ्री ज़ोन), भारतीय उद्यमियों और निवेशकों के साथ कई रणनीतिक बैठकों का आयोजन हुआ, जिसमें भारत मार्ट जैसे महत्वाकांक्षी वैश्विक व्यापार केंद्र को लेकर सहमति भी बनी।

टूटे तार से करंट लगा 11 पशुओं की मौत

पशुपालक बोले- शिकायतें गंभीरता से नहीं लेती बिजली कंपनी

सतना (नप्र)। सतना में बरसात के मौसम में बिजली विभाग की लापरवाही से दो अलग-अलग घटनाओं में 11 पशुओं की मौत हो गई। कोठी थाना क्षेत्र के भैंसवार में आठ गोवंश और जसो थाना क्षेत्र के झिंगोदर में तीन भैंसों की करंट लगने से जान चली गई।

ग्रामीणों ने बताया कि भैंसवार में बिजली का तार टूटकर गिरने के बाद अधिकारियों को सूचना दी गई थी। लेकिन, न तो बिजली काटी गई और न ही कोई मरम्मत की गई। इसके परिणामस्वरूप गांव में घूम रहे आठ गोवंश करंट की चपेट में आ गए। स्थानीय लोगों का कहना है कि घटना के बाद भी विभाग ने कोई सुधार कार्य नहीं किया।

लाखों का हुआ नुकसान

इसी तरह झिंगोदर में किसान इंद्रपाल की तीन भैंसों की करंट लगने से मौत हो गई। इस घटना से किसान को लगभग ढाई से तीन लाख रुपए का नुकसान हुआ है। किसान का आरोप है कि बिजली कंपनी सूचनाओं को गंभीरता से नहीं लेती है, जिसके कारण इस तरह की दुर्घटनाएं लगातार हो रही हैं।

खेत में बने तालाब में डूबे 3 भाई-बहन, मौत

छतरपुर में स्कूल से लौटकर आम तोड़ने गए थे, 10 से 4 साल तक की उम्र

छतरपुर (नप्र)। छतरपुर में तीन बच्चों की डूबने से मौत हो गई। तीनों आपस में भाई-बहन हैं। हादसा सोमवार को लवकुश नगर के हटवां गांव का है।

पिता प्रतिपाल सिंह ने पुलिस को बताया कि तीनों बच्चे- लक्ष्मी (10), तनु (8) और लोकेंद्र (4) स्कूल से लौटकर घर आए थे। फिर खेत में लगे पेड़ से आम तोड़ने की बात कहकर निकल गए। रात साढ़े 8 तक नहीं लौटे तो परिजन ढूंढने निकले। यहां खेत में बने तालाब में तीनों के शव दिखे।

फिसलकर तालाब में गिरने की आशंका

परिजन के मुताबिक, आम के पेड़ से फल तोड़ने के दौरान बच्चे तालाब के पास पहुंचे और फिसलकर पानी में गिर गए। रात करीब 9:30 बजे परिजन ने पुलिस को सूचना दी। बच्चों को तत्काल बारीगढ़ अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

परिजन के बयान बाकी

बीएमओ एसएस चौहान ने बताया कि लवकुश नगर अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद शव परिवार को सौंप दिए गए हैं। वहीं, एसडीओपी नवीन दुबे ने बताया कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। परिजन का बयान लेकर आगे की कार्रवाई करेंगे।

भोपाल की टूटी सड़कों पर बिछाए पेवर ब्लॉक्स

बीजेपी दफ्तर-आरकेएमपी के सामने भरे गड्ढे 10 नंबर-करोंद में भी मरम्मत

भोपाल (नप्र)। बारिश की वजह से राजधानी भोपाल की सड़कें जर्जर होने लगी हैं। कई सड़कों के हाल बुरे हैं और उन पर एक से डेढ़ फीट तक गहरे गड्ढे हो गए हैं। पीडब्ल्यूडी अफसर इन सड़कों की अब मरम्मत करा रहे हैं। मंगलवार को बीजेपी दफ्तर और रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के सामने टूटी सड़कों पर पेवर ब्लॉक बिछाए गए। इस सड़क का बड़ा हिस्सा जर्जर हो गया था। जिससे हादसे का खतरा भी था। पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह के निर्देश के बाद सोमवार को इंजीनियर इन चीफ केपीएस राणा और भोपाल सर्किल के चीफ इंजीनियर संजय मस्के ने शहर की पांचों डिवीजन की उन सड़कों का निरीक्षण किया, जहां गड्ढों की शिकायत थी। निरीक्षण के बाद निचले अमले को तेजी से काम करने के निर्देश दिए गए थे। इसके चलते अगले दिन यानी, मंगलवार से ही सड़कों की मरम्मत शुरू हो गई।

ग्वालियर, शाजापुर में बारिश रायसेन में सड़कों पर भरा पानी

प्रदेश में नदियां उफनीं, बाढ़ के हालात

भोपाल (नप्र)। मध्यप्रदेश में 16 जून को मानसून की एंट्री के बाद अब तक प्रदेश में 18 इंच बारिश हो चुकी है। कई जिलों में बाढ़ के हालात है। मंगलवार को दोपहर के बाद ग्वालियर, शाजापुर समेत 9 जिलों में तेज पानी गिरा। रायसेन में 20 मिनट की बारिश में सड़कों पर पानी भर गया। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों में भोपाल, इंदौर समेत प्रदेश के 30 से ज्यादा जिलों में बारिश की अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में अब तक कोटे की आधी बारिश हो चुकी है। निवाड़ी में तो 103 प्रतिशत तक पानी गिर चुका है। मंडला, टीकमगढ़ में भी बारिश का कोटा 75 प्रतिशत तक फुल हो गया है। अगले 4 दिन यानी 18 जुलाई तक तेज बारिश का दौर चलेगा।

इन जिलों में बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग के अनुसार बालाघाट, सिवनी, मंडला, डिंडौरी, सिंगरौली और सीधी में भारी बारिश का दौर जारी है। वहीं, अगले कुछ घंटों में बैतूल, सतना, रीवा, मऊगंज, सागर, दमोह, छतरपुर, देवास, शिवपुरी, भिंड, उमरिया, राजगढ़, पांढुर्णा में मध्यम और भोपाल, पन्ना में हल्की बारिश होने की संभावना है।

इसी तरह टीकमगढ़, निवाड़ी, अनूपपुर, शहडोल, ग्वालियर, श्योपुर, मुरैना, दतिया, कटनी, मैहर, इंदौर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, धार, मंदसौर, उज्जैन, विदिशा, रायसेन, नर्मदापुरम, नरसिंहपुर, जबलपुर, सीहोर, शाजापुर और बुरहानपुर में भी हल्की बारिश हो सकती है।

'नशे से दूरी है जरूरी' अभियान का शुभारंभ

नशा केवल स्वास्थ्य नहीं सामाजिक ताने-बाने को भी करता है छिन्न-भिन्न : सीएम

डीजीपी मकवाना ने मुख्यमंत्री के संदेश एवं अभियान के पोस्टर का किया विमोचन, 30 जुलाई तक चलेगा राज्य स्तरीय अभियान

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि नशा एक सामाजिक बुराई है। जो युवाओं, परिवार और समाज की जड़ों को खोखला बना रही है। नशे की जद में आकर कई परिवार उजड़ जाते हैं। नशा नाश की जड़ है, जो न केवल स्वास्थ्य को खत्म करता है बल्कि सामाजिक ताने-बाने को भी छिन्न-भिन्न करता है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेश में मंगलवार से 30 जुलाई तक प्रारंभ हुए नशामुक्ति अभियान - 'नशे से दूरी है जरूरी' के शुभारंभ अवसर पर वीडियो संदेश के माध्यम से यह विचार व्यक्त किए।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि यह अत्यंत दुःखद है कि युवाओं के बीच नशे का चलन तेजी से बढ़ रहा है। युवा देश का भविष्य हैं, उन्हें इस दलदल से बचाने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह संकल्पित है। 'नशे से दूरी है जरूरी' अभियान चलाने का उद्देश्य न केवल नशे को रोकना है बल्कि समाज में नई चेतना जागृत करना भी है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेशवासियों से म.प्र. पुलिस द्वारा संचालित नशा मुक्ति अभियान को सफल बनाने का आहवान किया है।

डीजीपी ने किया अभियान का शुभारंभ- पुलिस महानिदेशक श्री कैलाश मकवाना ने पुलिस मुख्यालय, भोपाल में मंगलवार को वृहद नशा मुक्ति जन-जागरूकता अभियान ''नशे से दूरी-है जरूरी'' का शुभारंभ किया। उन्होंने मुख्यमंत्री डॉ. यादव के वीडियो संदेश तथा अभियान के पोस्टर का विमोचन भी किया।

आपात स्थितियों से निपटने एम्स अस्पताल अधिकारियों का प्रशिक्षण

भोपाल। एम्स भोपाल में कार्यपालक निदेशक प्रो. (डॉ.) अजय सिंह के मार्गदर्शन में 'स्वास्थ्य आपात स्थितियों हेतु अस्पताल प्रशासनिक अधिकारियों की क्षमता संवर्धन' विषय पर एक महत्वपूर्ण छह दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। यह प्रशिक्षण सामुदायिक एवं पारिवारिक चिकित्सा विभाग (CFM) एवं अस्पताल प्रशासन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थितियों के दौरान अस्पतालों की तैयारियों को सुदृढ़ बनाना है। कार्यक्रम में सामुदायिक एवं पारिवारिक चिकित्सा विभाग के प्रमुख ने ऐसे प्रशिक्षण की उपयोगिता को रेखांकित किया। इसके पश्चात एम्स भोपाल के आपदा प्रबंधन हेतु नामित नोडल अधिकारी ने प्रशिक्षण की पृष्ठभूमि, संरचना और प्रमुख उद्देश्यों की जानकारी साझा की। मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित एम्स भोपाल के कार्यपालक निदेशक प्रो. (डॉ.) अजय सिंह ने अपने संबोधन में कहा, 'आपात स्थितियाँ केवल नैदानिक नहीं, बल्कि संपूर्ण प्रणाली की चुनौती होती हैं। ऐसे में अंतरविभागीय समन्वय, व्यवहारिक प्रशिक्षण और अस्पताल स्तर पर मॉक ड्रिल जैसी गतिविधियाँ अत्यंत आवश्यक हैं। यह प्रशिक्षण केवल कक्षा तक सीमित नहीं रहना चाहिए, इसकी असली परीक्षा फील्ड पर होती है, जहाँ त्वरित, प्रभावी और समन्वित प्रतिक्रिया जीवन रक्षा में सहायक होती है।' उन्होंने यह भी कहा कि प्रत्येक संस्थान को एक लचीली, उत्तरदायी और सतत् तैयार रहने वाली स्वास्थ्य प्रणाली विकसित करनी चाहिए, जो महामारी, प्राकृतिक आपदाओं एवं सामूहिक दुर्घटनाओं जैसी स्थितियों में सशक्त रूप से कार्य कर सके। इस अवसर पर एसोसिएट डीन (शैक्षणिक) ने आपदा प्रबंधन के अपने गहन अनुभव साझा करते हुए ओडिशा रेल दुर्घटना का उल्लेख करते हुए कहा कि ओडिशा ट्रेन हादसे जैसे गंभीर हालातों में त्वरित निर्णय, विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय और अस्पतालों की सर्ज कैपेसिटी ही जीवन बचाने में निर्णायक साबित होती हैं। कार्यक्रम का समापन अस्पताल प्रशासन विभाग के अध्यक्ष द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ।

युवक को 20 सेकेंड में तीन ट्रकों ने रौंदा

दोनों पैर सड़क पर चिपक गए, ग्वालियर में बेटी की सगाई के एक दिन पहले मौत

ग्वालियर (नप्र)। ग्वालियर में एक 47 वर्षीय शख्स को तीन ट्रक रौंदते हुए निकल गए। पूरा घटनाक्रम महज 20 सेकेंड में हुआ। घटना रविवार रात करीब 2 बजे की है। सोमवार को इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। मंगलवार को उनकी बेटी की सगाई होनी थी।

हादसा एबी रोड पर रामद्वारा के पास लक्ष्मीगंज पुलिया पर हुआ। देवेंद्र जाटव होटल से सब्जी लेने जा रहे थे। इसी दौरान एक ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी। वे सड़क पर गिर गए। रिमझिम बारिश में लगातार दो ट्रक देवेंद्र के ऊपर से गुजर गए। उनके दोनों पैर सड़क से चिपक गए। उन्हें ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया।

होनी थी बड़ी बेटी की सगाई

गोल पहाड़िया नवग्रह कॉलोनी के रहने वाले देवेंद्र जाटव की बड़ी बेटी की सगाई मंगलवार को यानी आज होनी थी। वे आज बेटी के होने वाले ससुराल जाने वाले थे। उनके भाई गजेंद्र जाटव (39) ने जनकगंज थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि रविवार रात करीब 2 बजे भाई लक्ष्मीगंज से बहोड़ापुर की ओर जा रहे थे। लक्ष्मीगंज पुलिया पर हादसा हो गया। भाई की तब सांसें चल रही थीं। सूचना मिलने पर मैं मौके पर पहुंचा और पुलिस की मदद से उन्हें ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया। सोमवार को उनकी मौत हो गई।

कलर-पुट्टी का ठेका लेता था देवेंद्र

गजेंद्र ने बताया, भाई की दो बेटियां और एक बेटा है। देवेंद्र कलर-पुट्टी का ठेका लेकर काम करते थे। रविवार को वे घाटीगांव से काम कर लौटे थे। उनकी पत्नी अपनी बहन के ससुराल डबरा गई थीं। भाई घर पहुंचे और बेटी से खाना मांगा। बेटी ने कहा कि रोटी है, लेकिन सब्जी नहीं है। ऐसे में वे देर रात सब्जी लेने होटल के लिए निकल पड़े। आसपास के होटल बंद होने के कारण वे थोड़ा आगे निकल गए। जब वे देर तक घर नहीं लौटे तो उनका बेटा उन्हें ढूंढने के लिए निकला। कुछ देर बाद हादसे की जानकारी मिली। दो बेटियां और एक बेटा है।

पास के सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ हादसा

जनकगंज पुलिस ने बताया कि घटनास्थल के पास एक शराब दुकान के सीसीटीवी कैमरे में पूरा हादसा रिकॉर्ड हुआ है। फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे सिर्फ 20 सेकेंड में एक के बाद एक तीन ट्रक देवेंद्र के ऊपर से गुजरते हैं। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हादसे में शामिल ट्रकों की पहचान की जा रही है। फिलहाल जांच जारी है।

कलेक्ट्रेट की छत से कूदने लगी महिला, पुलिस ने बचाया

देवास में जमीन पर कब्जे की शिकायत लेकर आई थी, एसडीएम बोले- ये राजनीति प्रेरित

देवास (नप्र)। देवास में मंगलवार को एक महिला ने कलेक्ट्रेट भवन की छत से कूदने के लिए दौड़ लगा दी। हाटपिपल्या की रहने वाली आशा बाई जनसुनवाई में पहुंची थी। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने समय रहते आशा को कूदने से रोक लिया। जमीन विवाद को लेकर वह अपने पति के साथ कई बार आवेदन दे चुकी है, लेकिन कार्रवाई नहीं होने से वह नाराज थी।

आशा और उसके पति धर्मेंद्र बागरी का कहना है कि उनकी जमीन किसी और को फर्जी तरीके से दे दी गई है। वे कई महीनों से कलेक्टर कार्यालय में आवेदन दे रहे हैं, लेकिन अब तक किसी स्तर पर सुनवाई नहीं हुई। महिला ने कहा कि अगर आगे भी कोई सुनवाई नहीं हुई तो वह आत्मदाह जैसा कदम उठाएगी।

एसडीएम बोले- मामले में राजनीति की जा रही- एसडीएम बिहारी सिंह ने बताया कि महिला द्वारा किया गया प्रयास राजनीति से प्रेरित है। अधिकारी महिला और उसके पति की बातों को सुन रहे हैं और मामले की जांच की जा रही है। संबंधित अधिकारियों से चर्चा कर दस्तावेजों की स्थिति समझी जा रही है।

कलेक्टर बोले- मामला पुराना और जटिल- कलेक्टर ऋतुराज सिंह ने बताया कि यह मामला काफी पुराना और जटिल है। शिकायतकर्ता को साल 1960 में जमीन का पट्टा जारी किया गया था, लेकिन उसी खसरा नंबर पर करीब 30-35 साल पहले आईटीआई का निर्माण हो गया।

अधिकारी इस जमीन को सरकारी भूमि बता रहे- धर्मेंद्र ने बताया कि अब अधिकारी इस जमीन को शासकीय भूमि बता रहे हैं। मामले की शिकायत सीएम हेल्पलाइन 181 पर भी की थी, लेकिन 10 महीने बाद भी कोई समाधान नहीं हुआ है। तहसील कार्यालय अब इस जमीन को बागली क्षेत्र में दिखा रहा है, जबकि असली जमीन हाटपिपल्या में ही है।

किसी ने फर्जी तरीके से रजिस्ट्री करवा ली

आशा के पति धर्मेंद्र बागरी ने 2024 से लगातार कई बार आवेदन दिए। 2024 में कलेक्टर को दिए आवेदन में बताया था कि दादी नबी बाई की जमीन पर किसी ने फर्जी तरीके से रजिस्ट्री करवा ली है। 16 बीघा यह जमीन हाटपिपल्या में है। दादी का निधन साल 2014 में हो गया था। इसके बाद धर्मेंद्र रोजगार के लिए गुजरात चला गया।

जब धर्मेंद्र लौटा तो पता चला कि उसकी दादी की जमीन किसी और के नाम पर हो गई है। धर्मेंद्र ने बताया कि जमीन के पुराने दस्तावेजों से छेड़छाड़ की गई है।